Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ● Friday, 13 September 2024 ● Year : 02 ● Issue : 236 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

झारखण्ड मुख्यमंत्री
मंईयां
सम्मान योजना

हर बहना को
हर साल
₹12 हजार

18 से 20
वर्ष की बहन-बेटियों
को भी योजना से लाभ

48,15,048 बहनों
का योजना के तहत
हुआ निबंधन

45,36,597 बहनें
सम्मान राशि से
अबतक आच्छादित

हर महीने की
15 तारीख तक
हर बहन के खाते में
पहुँचेगी सम्मान राशि

लुगु बुरु घंटाबाड़ी धोरोम गाढ़
की पवित्र भूमि लालपनिया से

करम पर्व
की पूर्व संध्या पर लाखों बहनों को
खुशियों का उपहार

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) की

दूसरी किस्त
का होगा हस्तांतरण

13 सितंबर, 2024 | अपराह्न 12:30 बजे से
ललपनिया फुटबॉल मैदान, गोमिया, बोकारो

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार

BRIEF NEWS

15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन की राज्यवासियों को मिलेगी सौगात

RANCHI : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश को नई सौगात देंगे। इसमें 11 नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से जमशेदपुर में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही अन्य जगहों से 10 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी शुरू होगा। टाटानगर स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर से सरकारी योजनाओं की सौगात देशवासियों को देंगे।

सचिवालय में तीसरे दिन भी ठप रहा कामकाज

RANCHI : सचिवालय में तीसरे दिन भी कामकाज ठप रहा। सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले सचिवालय सेवा के पदाधिकारी-कमार्चारी गुरुवार को भी सामूहिक अवकाश पर रहे। तीन दिनों में फाइलों का अंबार लग गया। लगभग 10 हजार फाइलों का मूवमेंट पूरी तरह से रूक गया। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद से बताया कि कल से सचिवालय सेवा के पदाधिकारी-कर्मचारी काम पर वापस लौटेंगे। इसके बाद आगे की ?णनीति बनाई जाएगी। बताते चलें कि सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी-करर्मचारी अपनी छह सूत्री मांगों को लेकर पिछले तीन महीने से आंदोलनरत हैं।

ज्वेलरी दुकान से साढ़े दस लाख के जेवरात ले उड़े चोर

RANCHI : नामकुम थाना क्षेत्र के सिदरौल जोड़ा मंदिर के समीप मां भवानी ज्वेलर्स दुकान में चोरी का मामला गुरुवार को प्रकाश में आया है। इस संबंध में गुड्डू सोनी ने नामकुम थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार चोरों ने दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर दुकान का दीवार काटकर साढ़े दस लाख का सामान लेकर फरार हो गये है। इन सामानों में एक किलो सोना और साढ़े चार किलो चांदी के सामान शामिल हैं।

लड़की को अकेला देख चाकू दिखा की छिनतई

RANCHI : एक लड़की से चाकू के बल पर मोबाइल की छिनतई कर रहे एक अपराधी को पब्लिक ने मौके पर ही पकड़ कर जम कर धुनाई कर डाली। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर स्थित श्रीनगर चौक के समीप एक अपराधी ने दिनदहाड़े चाकू के बल पर एक लड़की से मोबाइल छीन लिया। लड़की ने जब शोर मचाया तो मौके पर स्थानीय लोग जुट गए और मोबाइल छीन कर फरार होने की कोशिश कर रहे अपराधी को खदेड़ कर दबोच लिया। जैसे ही अपराधी स्थानीय लोगों की पकड़ में आया भीड़ ने उसकी जम कर धुनाई कर डाली। यहां तक कि जिस लड़की के साथ चाकू के बल पर अपराधी ने मोबाइल छीना उस लड़की ने भी उसे जमकर पीटा।

26001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति का मामला

सरकार व सीटेट की बहस पूरी सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

PHOTON NEWS RANCHI : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट (जेटेट) पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास झारखंड निवासी अभ्यर्थी को शामिल करने के मामले में एसएलपी दाखिल पर गुरुवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में लगातार तीन दिनों तक बहस चली। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता वी मोहना एवं झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा है। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फार्म का तिथि बंद हो चुकी थी, उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के आए आदेश का अनुपालन करते हुए

नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। जबकि नियमानुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अहर्ता के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और जेएससीसी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने 26001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी।

अग्रवाल बंधु हत्याकांड

लोकेश के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी की जमानत पर पूरी हुई सुनवाई

RANCHI : लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या मामले में मुख्य साजिशकर्ता लोकेश कुमार चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र कुमार तिवारी की ओर से दायर क्रिमिनल अपील की सुनाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में धर्मेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जमानत का आग्रह करते हुए दायर हस्तक्षेप याचिका (आईए) पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। जिसके बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोप है कि धर्मेंद्र ने लोकेश के कहने पर अपनी बंदूक से गोली चलाई थी जिससे चर्चित हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की मौत हो गई थी। धर्मेंद्र आर्मी से सेवानिवृत हुआ था वह लोकेश चौधरी के यहां उनके बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। पुलिस की जांच में यह बात आई थी कि गोली धर्मेंद्र कुमार के राइफल से ही चली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर बरामद खोखा एवं धर्मेंद्र के राइफल दोनों की जांच की थी। मामले में लोकेश चौधरी की जमानत पूर्व में हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल, इस हत्याकांड में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने जून 2023 में लोकेश कुमार चौधरी, सुनील सिंह, धर्मेंद्र कुमार तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लोकेश और धर्मेंद्र ने निचली अदालत द्वारा सुनाई सजा को हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर कर क्रिमिनल अपील तैयार कर चुनौती दी है। लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को अशोक नगर स्थित एक न्यूज कार्यालय में 6 मार्च 2019 को बुलाया था। विवाद होने पर उनकी हत्या गोली मार कर की गयी थी। मामले को लेकर अरगोड़ा थाना के प्राथमिकी दर्ज हुई थी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश कुमार चौधरी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार रहा था । दिसंबर 2020 में उसने कोर्ट में सरेंडर किया था।

ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में सरकार ने मांगा समय

PHOTON NEWS RANCHI : सीएम हेमंत सोरेन की शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी थाना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को देने का आग्रह करने वाले ईडी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की थी। मामले में प्रतिवादी सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल किया, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास और सौरभ कुमार ने पैरवी की। ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आग्रह किया गया है कि इस मामले में गोंदा पुलिस द्वारा ईडी के अधिकारी को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई

या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौपा जाए। हालांकि पूर्व में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में दर्ज कांड संख्या 06/2024 को चुनौती देने वाली ईडी के अधिकारियों कपिल राज एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी के अधिकारियों को गोंदा पुलिस द्वारा 41 ए के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। कोर्ट ने ईडी अधिकारी को खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखा है। बता दें कि यह एफआईआर झारखंड पुलिस द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत रांची के एससी/एसटी पुलिस थाना में दर्ज की गई है। यह एफआईआर हेमंत सोरेन सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत को लेकर की गई है।

रांची नगर निगम से हाईकोर्ट ने मौखिक कहा-

बगैर नक्शा स्वीकृति के चल रहे रूफ टॉप बार-रेस्टोरेंट का संचालन करें बंद

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा कि, राजधानी रांची में बगैर मैप स्वीकृति के चल रहे हैं रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को तत्काल बंद करें। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रांची नगर निगम से मौखिक कहा कि लालपुर क्षेत्र में कई रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मैप की स्वीकृति भी नहीं ली है, रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट पर अंकुश लगाकर रांची नगर निगम एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि रांची में अधिक संख्या में रूफ टॉप बार रेस्टोरेंट

चल रहे हैं, इन्हे बंद किया जाय। कोर्ट ने मौखिक कहा की रांची के हरमू रोड स्थित रेस्टोरेंट के पास पार्क में गांजा, अफीम, चरस जैसे मादक पदार्थों की बिक्री होती है, इसे रोका जाए। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की। कोर्ट ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अधिवक्ता को कावस रेस्टोरेंट के पास पार्क को रांची नगर निगम को दो सप्ताह में हस्तांतरित करने का निर्देश भी दिया है। ताकि रांची नगर निगम द्वारा यहां जल्द से जल्द टेंडर कर पार्क का सौंदर्यीकरण संभव हो सके। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर निर्धारित की है। इससे पहले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि रांची सहित पूरे राज्य में गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थ की बिक्री रोकने को लेकर अभियान चल रहा है। प्रतिदिन मादक पदार्थों के तस्कर पकड़े जा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को अफीम, चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया है।

मनमोहन कुमार बने रांची एरिया बोर्ड के नए जीएम, डीएन साहू नए एसई

जेबीवीएनएल के जीएम पीके श्रीवास्तव समेत 16 बिजली अफसरों का हुआ तबादला

PHOTON NEWS RANCHI : जेबीवीएनएल के रांची एरिया बोर्ड जीएम (महाप्रबंधक) पीके श्रीवास्तव समेत 16 बिजली अफसरों का तबादला कर दिया गया है। पीके श्रीवास्तव का तबादला निगम मुख्यालय में महाप्रबंधक (सेल एंड प्रचेज) में कर दिया गया है। वहीं जमशेदपुर एरिया बोर्ड के जीएम श्रवण कुमार को महाप्रबंधक एपीटी निगम मुख्यालय, धनजंय कुमार महाप्रबंधक एपीटी को निगम मुख्यालय में जीएम आईटी और निगम मुख्यालय के महाप्रबंधक तकनीकी सुनील कुमार को जीएम मेदिनीनगर एरिया बोर्ड के पद पर

पदास्थापित किया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है। जीएम के अलावा कई डिप्टी जीएम का भी तबादला किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, उपमहाप्रबंधक डालटेनगंज मनमोहन कुमार को उप महाप्रबंधक रांची के अतिरिक्त रांची एरिया बोर्ड के जीएम का प्रभार दिया गया है। वहीं अजीत कुमार (सेल प्रचेज) निगम मुख्यालय को जमशेदपुर एरिया बोर्ड का उपमहाप्रबंधक राजस्व के अतिरिक्त जमशेदपुर एरिया बोर्ड का जीएम का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। दीपक कुमार जमशेदपुर अंचल को उपमहाप्रबंधक निगम मुख्यालय बनाया गया है। इन्हें महाप्रबंधक तकनीकी निगम मुख्यालय का भी अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। जेबीवीएनएल के प्रभारी जीएम आईटी और उपमप्रबंधक स्टोर एवं टीआरडब्लू संजय सिंह को उप महाप्रबंधक पावर प्रचेज निगम मुख्यालय के अतिरिक्त महाप्रबंधक तकनीकी मुख्यालय बनाया गया है। उप महाप्रबंधक चास डीएन साहू को रांची बिजली आपूर्ति सर्किल, विभा कुमारी को राजस्व रांची को प्लानिंग मुख्यालय, गिरिडीह सर्किल के विनय कुमार सिन्हा को कोडरमा सर्किल, रांची सर्किल के दिनेश कुमार सिंह को चास सर्किल, कोडरमा सर्किल के सुधांशु को टीआरडब्लू रांची, सुधीर कुमार को निगम मुख्यालय से जमशेदपुर सर्किल, मुकुल कुमार को हजारीबाग से रामगढ़ सर्किल और संतोष कुमार सिन्हा को रामगढ़ से हजारीबाग सर्किल में तबादला कर दिया गया है।

बकरी चराने गए वृद्ध पर भेड़ियों ने किया हमला

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के बुढ़मू में भेड़ियों के हमले से 2 लोग घायल हो गये। घटना बुधवार शाम बिंजा गांव की है। दोनों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। उन्हें एंटीरेबीज का इंजेक्शन दे दिया गया है।

फिलहाल दोनों की स्थिति स्थिर बतायी जा रही है। घायलों में बैजा भुइंया 55 साल और बहुरा गंझू 50 साल शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन में बैजा भुइंया बहुरा गंझू जंगल में बकरी चराने गये थे। इस

दौरान वे सूखी लकड़ी चुनने के लिए जंगल के अंदर चले गये थे। इसी बीच दो भेड़िये उनकी बकरी के पास पहुंच गये। बकरियों की आवाज सुनकर वे उधर भागे तो भेड़ियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया। उनकी चीख सुनकर ग्रामीण जंगल की ओर गये तो देखा कि वे लहूलूहान पड़े हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी।

पिठोरिया में अधिकारियों ने फरियादियों से आवेदन लेकर दोनों पक्षों की सुनी बातें

PHOTON NEWS RANCHI : डीजीपी अनुराग गुप्ता के निदेर्शानुसार राची पुलिस के बैनर तले जिले के सभी थानों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को पिठोरिया थाना परिसर में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर सैकड़ों फरियादी अपनी फरियाद लेकर जन शिकायत कार्यक्रम में पहुंचे। मौजूद अधिकारियों ने फरियादियों से आवेदन लेकर दोनों पक्षों की बात सुनी। बहुत से मामलों को त्वरित निपटारा

फरियाद सुनते अधिकारी।

किया। अन्य मामले जिनपर अनुसंधान की आवश्यकता है, उसके लिए अनुसंधानकर्ता नियुक्त कर कार्रवाई के लिए आदेश दिया। मौके पर भूमि से संबंधित ज्यादा मामले जन शिकायत कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद कांके सीओ जयकुमार राम ने भूमि से संबंधित शिकायतों को जल्द निष्पादित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यालय एक के पुलिस उपाधीक्षक अमर कुमार पांडे ने बताया कि झारखंड डीजीपी के निदेर्शानुसार रांची पुलिस के बैनर तले जन शिकायत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्राइम से संबंधित मामलों पर ऑन द स्पोर्ट एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

राज्य में 14 व 15 सितंबर को भारी बारिश होने की संभावना

PHOTON NEWS RANCHI : राज्य में आनेवाले दिनों में मौसम में बारिश का असर देखा जायेगा। 16 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की मानें तो 13 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि अन्य हिस्से में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसमें दुमका, गोड्डा, गढ़वा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, साहेबगंज में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, 14 और 15 सितंबर को मध्य, दक्षिणी पश्चिम और उत्तर पूर्व में भारी बारिश की जानकारी दी गयी है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी

जारी किया है। इसके तहत दुमका, गोड्डा, गढ़वा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, साहेबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां समेत अन्य जिलों में भारी बारिश की जानकारी दी गयी है। इस दौरान इन जिलों में भारी बारिश के साथ ही वज्रपात के लिए भी चेतावनी जारी की गयी है।

बोले चिकित्सक- अपने घर और आसपास में पानी न होने दें जमा, लगातार बरतें सावधानी

राज्य भर में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू

PHOTON NEWS RANCHI : एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी डेंगू तेजी से राज्य के कई जिलों में पांव पसार रहा है। राजधानी के अलग-अलग निजी और सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लक्षण के साथ पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जहां अलर्ट मोड में हैं तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर इससे बचाव के उपाय भी लोगों को बता रहे हैं।

झारखंड में वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल के नोडल पदाधिकारी डॉ बीके सिंह ने बताया कि इस वर्ष राज्य के गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा जिले को छोड़ बाकी के 21 जिलों में डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा 122 डेंगू

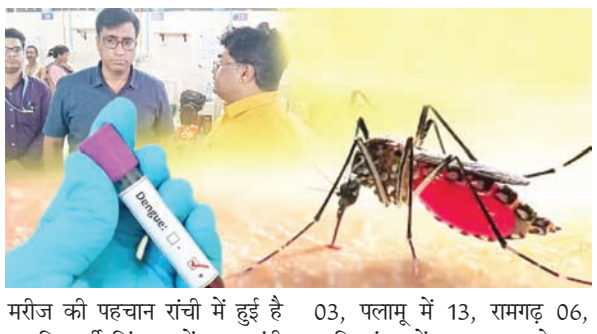

मरीज की पहचान रांची में हुई है जबकि पूर्वी सिंहभूम में 66, खूंटी में 59 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार बोकारो में 09, चतरा में 05, देवघर में 06, धनबाद में 09, दुमका में 01, गढ़वा में 16, गिरिडीह में 18, गुमला में 08, हजारीबाग में 20, कोडरमा में 04, लातेहार में 04, लोहरदगा में 03, पलामू में 13, रामगढ़ 06, साहिबगंज में 24, सरायकेला-खरसावां में 15, सिमडेगा में 04 और पश्चिमी सिंहभूम में 24 डेंगू के कंफर्म केस मिल चुके हैं।

डॉ अजीत ने बताया कि डेंगू के प्रसार के लिए एडीज मच्छर मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। एडीज मच्छर की खासियत यह है कि इसका लार्वा साफ और बहुत दिन से स्टोर किये पानी में पनपता है। ऐसे में अपने घर और आसपास में, कूलर में, खराब हो चुके टायर या डिब्बे में पानी नहीं जमा होने दें। डॉ अजीत ने बताया कि एडीज मच्छर ज्यादातर दिन में ही ज्यादा एक्टिव रहता है इसलिए दिन के समय भी मच्छरों से बचाव जरूरी है।

लक्षण

एडीज मच्छर के काटने से होने वाले डेंगू में संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार और पूरे शरीर में तेज दर्द होता है। संक्रमित व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है और मरीज बहुत कमजोरी महसूस करता है। शरीर में प्लेटलेट्स की कमी की वजह से बीमार व्यक्ति के शरीर पर जगह जगह चकता-चकता दिखने लगता है। सदर अस्पताल में चिकित्सक डॉ अजीत कुमार कहते हैं कि ज्यादातर मामलों में डेंगू का संक्रमण स्वयं समाप्त हो जाता है लेकिन कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाने से रक्तस्राव की वजह से स्थिति गंभीर हो जाती है।

ऐसे करें बचाव

झारखंड में वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर बीके सिंह ने बताया कि डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह एक्टिव है। नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित कर मच्छरों की रोकथाम का अभियान चलाया जा रहा है। लावारीधी दवाओं का छिड़काव और मच्छररोधी दवाओं का छिड़काव प्रभावित इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन दिनों डेंगू के केस बढ़े हैं लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

धनबाद ड्रैगन्स ने जीता वीमेंस टी-20 का खिताब, शशि माथुर बनीं प्लेयर ऑफ द मैच

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) द्वारा आयोजित झारखंड वीमेंस टी20 लीग के फाइनल में रोमांचक मुकाबले में धनबाद ड्रैगन्स ने रांची रॉयल्स को 5 विकेट से मात देकर चैंपियन बना। बता दें कि धनबाद ड्रैगन्स पूरी प्रतियोगिता में अपराजय रही। प्रतियोगिता की विजेता टीम धनबाद ड्रैगन्स की ट्रॉफी के साथ 1 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया।

वहीं उपविजेता टीम रांची रॉयल्स को ट्रॉफी के साथ 80 हजार का नगद पुरस्कार दिया गया। गुरुवार को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जेएससीए के मुख्य मैदान में खेला गया। रांची रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20

ओवर में 5 विकेट खोकर 116 रन बनाए। रांची की ओर से टीम की कप्तान रश्मि गुड़िया ने सर्वाधिक 45 रन बनाए। वहीं संध्या कुमारी ने 33 और प्रियंका सवाइयां ने 26 रनों की पारी खेली। धनबाद की ओर से दुर्गा मुर्मू ने 2 विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद ड्रैगन्स ने 19।3 ओवर में 5 विकेट खोकर 117 रन बनाकर मुकाबले को जीत लिया। धनबाद ड्रैगन्स की ओर से सलामी बैटर शशि माथुर ने 50 रन बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं कप्तान दुर्गा मुर्मू ने 24 रनों की पारी खेली। रांची की ओर से आनंदिता, नेहा, प्रियंका और शैंपी ने 1- 1 विकेट झटके। मुकाबले में शानदार पारी खेलने वाली धनबाद ड्रैगन्स की शशि माथुर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रांची जोन के आईजी अखिलेश झा, जेएससीए के प्रेसिडेंट संजय सहाय, वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र सिन्हा, सेक्रेटरी देवाशीष चक्रवर्ती, ज्वाइंट सेक्रेटरी पीएन सिंह ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया।

सुविचार
कला का उद्देश्य आत्मा को शिक्षित और उन्नत करना है।
– फ्रेडरिक शिलर

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Friday, 13 September 2024 ● Year : 02 ● Issue : 236 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

12
Shilpa Shetty Is Ageing Like A...

SHARE

संसेक्स	:	82,962.71
निफ्टी	:	25,388.90

SARAFA

सोना	:	6,875
चांदी	:	91.05

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

एकल पीठ का आदेश बरकरार, सुनवाई के बाद सुरक्षित था फैसला
निकाय चुनाव : सरकार की अपील खारिज

हाईकोर्ट

PHOTON NEWS RANCHI : गुरुवार को निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा है। पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर 4 जनवरी 2024 को आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी। पूर्व में हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट करने के बाद ही राज्य में निकायों का चुनाव करना है। राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी के आकलन की प्रक्रिया जारी है। पिछड़ा आयोग द्वारा ओबीसी की आबादी का आकलन किया जा रहा है। वहीं प्रतिवादी पूर्व पार्षद रोशनी खलखो की ओर से बताया गया कि सरकार राज्य के निकाय चुनाव को टाल रही है। सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है। एकल पीठ ने भी चुनाव के संबंध में उनके पक्ष में फैसला दिया है। दरअसल, तीन सप्ताह में राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने के 4 जनवरी 2024 के हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश को रद्द करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से अपील (एलपीए) दायर की गई थी।

तीन सप्ताह में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का चार जनवरी को दिया गया था ऑर्डर

ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मांगा था समय

अपील (एलपीए) में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यह राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन करेगी और इस संबंध में डाटा राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी। इसके आधार पर निकाय चुनाव में वार्डों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए निकाय चुनाव पूरा करने के लिए समय दिया जाए। राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश पर तत्काल रोक लगाने एवं एकल पीठ के आदेश को रद्द करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया था। अपील में राज्य सरकार ने झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के प्रोविजन का हवाला देते हुए नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति को सही ठहराया है। गौरतलब है कि राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की याचिका को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

पॉक्सो एक्ट के तहत मंत्री इरफान के खिलाफ दुमका कोर्ट में चलेगा ट्रायल

झारखंड की राजनीति में बड़बोलेपन के लिए चर्चित ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दुष्कर्म पीड़ित एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में मंत्री इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। दुमका कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने के मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि इरफान अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।

केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया- कुछ वर्षों में संथाल की डेमोग्राफी में आया बड़ा बदलाव

- आदिवासियों की संख्या में आई बड़ी गिरावट
- बढ़े मदरसे, मुस्लिमों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही एसपीटी एक्ट की जमीन

संथाल इलाके में बांग्लादेशी मूल के लोगों की घुसपैठ रोकने और इसकी जांच केझमामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने यह माना है कि पिछले कुछ वर्षों में संथाल की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है। केंद्र ने संथाल की मौजूदा परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि पिछले लगभग एक दशक में आदिवासियों की संख्या तेजी से घटी है। संथाल में आदिवासियों की संख्या कभी 44 प्रतिशत थी, जो अब घटकर 28 प्रतिश हो गई है। केंद्र ने कहा है कि इसमें सिर्फ घुसपैठ ही नहीं धर्मांतरण और पलायन भी शामिल है। केंद्र ने गंभीरता से बताया है कि संथाल में राज्य सरकार ही एसपीटी का वायलेशन कर रही है बाहर से लोग आ रहे हैं और घुसपैठ को संरक्षण दिया जा रहा है, ताकि वह यहां की जमीनों पर घुसपैठ कर सके। केंद्र ने बताया है कि बड़ी संख्या में गिफ्ट डीड के तहत जमीनों का हस्तांतरण हुआ है, जो यह दशार्ता है कि राज्य सरकार की सहमति के बगैर या नहीं हो सकता। केंद्र की ओर से यूआईडी ने भी जवाब दाखिल किया है और उन्होंने बताया कि आधार कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता।

BRIEF NEWS

400 साल पुरानी दीवार गिरी, सात लोगों की मौत

BHOPAL : गुरुवार को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रियासत कालीन राजगढ़ किले के नीचे के हिस्से वाली 400 साल पुरानी दीवार अचानक ढहकर कच्चे मकान और झोपड़ियों पर गिर गई। मलबे के नीचे नौ लोग दब गए, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मृतकों में पांच लोग एक ही परिवार के 5 सदस्य थे, जबकि दो दो लोग परिवार के मुखिया की बहन और बहनोई हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि बीते 30 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते किले की दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार अलसुबह करीब साढ़े तीन बजे तेज आवाज आई। लोग बाहर निकले तो देखा कि किले की दीवार गिर गई है। मलबे में दबे दो लोगों को तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जिस पर करीब साढे.पांच बजे कलेक्टर संदीप मकीन, एसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा, कोतवाली टीआई धीरेंद्र मिश्रा और एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे।

वियतनाम में यागी तूफान का कहर, अब तक 197 मरे

NEW DELHI : वियतनाम में यागी तूफान ने पिछले छह दिन में जमकर कहर बरपाया है। इस शक्तिशाली तूफान से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं। चौतरफा बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक कम से कम 197 नागरिकों को इस तूफान निगल लिया। इससे राजधानी हनोई भी अछूती नहीं है। इस तूफान से सर्वाधिक तबाही उत्तरी वियतमान में हुई है। मलेशिया के समाचार पत्र द सन के अनुसार, वियतनाम के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि शनिवार को आए यागी तूफान के कारण हुए भूस्खलन और व्यापक बाढ़ से कम से कम 197 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। वियतनाम को तीन दशक में पहली बार ऐसे शक्तिशाली तूफान का सामना करना पड़ा है।

9 अगस्त को अस्पताल में भर्ती हुए थे येचुरी
नहीं रहे सीपीएम महासचिव सीताराम, दिल्ली में निधन

- रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित कई नेताओं ने जताया शोक
- 'आइडिया ऑफ इंडिया' के संरक्षक थे येचुरी : राहुल

AGENCY NEW DELHI : गुरुवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। येचुरी को सीने में निमोनिया की तरह के संक्रमण के उपचार के लिए 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से यह जानकारी दी गई। उनकी हालत पिछले कुछ दिन से गंभीर बनी हुई थी और उन्हें कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर रखा गया था। येचुरी का निधन अपराह्न तीन बजकर पांच मिनट पर हुआ। येचुरी के निधन पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने शोक जताया है।

ग्रामीणों में दहशत का माहौल, डरे-सहमे दिख रहे सभी लोग
रांची में डायरिया का कहर, तमाड़ में तीन लोगों की चली गई जान

- तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने लिया संज्ञान
- कहा- गांव में जल्द लगाया जाएगा मेडिकल कैंप

PHOTON NEWS RANCHI : रांची जिले के सोनाहातू के बाद तमाड़ थाना क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया है। लोधमा गांव में डायरिया ने तीन लोगों की जान ले ली। मृतकों में मंगल मछुआ (53 वर्ष), उनकी पत्नी कुंती देवी (47 वर्ष) और बैशाखी देवी (41 वर्ष) शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, परिजनों ने इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद बेहतर उपचार के लिए रिम्स लें गए, जहां डॉक्टरों ने तीनो को मृत घोषित कर दिया गया। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने मामले पर संज्ञान लेते हुए रांची के सिविल सर्जन को मौत की सूचना दी है। उन्होंने जल्द गांव में मेडिकल कैंप लगाने के लिए कहा है। विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश महतो ने कहा कि विधायक लोधमा गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मिले। उन्होंने गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का आश्वासन दिया है। इधर, ग्रामीणों में डायरिया फैलने से दहशत का माहौल है, सभी लोग डरे और सहमे हुए हैं। बता दें कि झारखंड के कई जिलों में डायरिया मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां- जहां इसकी शिकायत मिल रही है, वहां पर मेडिकल कैंप लगाकर उनका

अग्निवीर गर्ल्स ने किया तरंग का फॉर्मेशन, प्रचंड हेलीकॉप्टर ने लगाया गोता

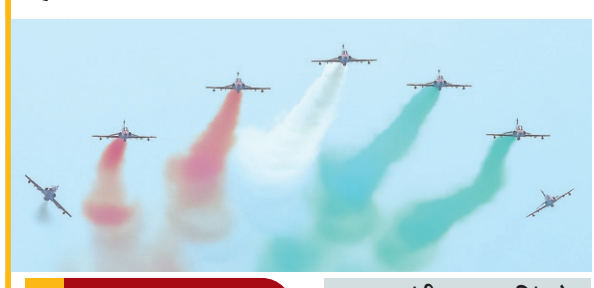

शक्ति अभ्यास

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एविएशन एक्सपो का किया उद्घाटन
- बोले- डिफेंस इंडस्ट्री में बढ़ाएं सहयोग

AGENCY JODHPUR : गुरुवार को राजस्थान के जोधपुर में 7 देशों की एयरफोर्स के तरंग शक्ति अभ्यास कार्यक्रम में फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर्स ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। जोधपुर एयरबेस पर दिन में करीब 11 बजे शुरू हुए एयर शो में सबसे पहले प्रचंड, सूर्य किरण, सारंग जैसे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने अलग-अलग फॉर्मेशन बनाए। वहीं अग्निवीर गर्ल्स की एक टुकड़ी ने तरंग का फॉरमेशन बनाया। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भारत के साथ अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और यूएई के एयरफोर्स चीफ भी शामिल हुए। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एविएशन एक्सपो का उद्घाटन किया। 14 सितंबर तक चलने वाले एक्सपो में स्वदेशी हथियारों सहित नई टेक्नोलॉजी से बने रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया।

रक्षा संबंधों को किया मजबूत : राजनाथ

राजनाथ सिंह ने कहा कि तरंग का अर्थ केवल लहर नहीं होता है, लहरों और तरंग तो कई लोगों की बातों में भी होती है। उन्होंने अपने पार्टनर देशों से कहा कि हमें डिफेंस पार्टनरशिप के साथ हार्ट टू हार्ट सिनर्जी बढ़ने की भी जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भारत के लोग शक्ति को पावर और फोर्स के रूप में ही नहीं देखते है, हमारे लिए शक्ति का अर्थ साक्षात जगदंबा भी होती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि तरंग शक्ति के माध्यम से हमने पार्टनर कंट्री के साथ अपने रक्षा संबंधों को और भी मजबूत किया है। हमारे बीच कई देशों के अधिकारी भी हैं। आप जब भी भारत आएं तो यहां की ऐरो स्पेस इंडस्ट्री को देखिए।

मोदी ने अपने आवास पर पैरालिंपिक पदक विजेताओं से की भेंट

- पेरिस खेलों में रिकॉर्ड 29 पदक जीतने के लिए दी बधाई

AGENCY NEW DELHI : गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार अपने आवास पर भारत के पैरालिंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें हाल ही में संपन्न पेरिस खेलों में रिकॉर्ड 29 पदक जीतने के लिए बधाई दी। खेल मंत्रालय द्वारा साझा किए गए 43 सेकेंड के वीडियो में प्रधानमंत्री को पैरालिंपियन पदक विजेताओं को बधाई देते और उनसे बात करते हुए देखा जा सकता है। इस बातचीत के दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय पैरालिंपिक समिति (पीसीआई) के प्रमुख देवेंद्र झाझडिया भी मौजूद थे। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल (एसएच1) स्पर्धा में लगातार दूसरा पैरालिंपिक स्वर्ण जीतने वाली निशानेबाज अवनि लेखरा और पैरालिंपिक पदक जीतने वाले भारत के पहले जूडो खिलाड़ी दृष्टिबाधित कपिल परमार उन लोगों में शामिल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाते देखा गया। परमार को प्रधानमंत्री मोदी से अपने पदक पर हस्ताक्षर करवाते देखा गया।

खिलाड़ियों ने किया है श्रेष्ठ प्रदर्शन

भारत ने पैरालिंपिक खेलों में 29 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जिसमें अभूतपूर्व सात स्वर्ण, नौ रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। पेरिस खेलों में भारत के 84 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया था और तीन साल पहले तोक्यो खेलों में हासिल किए गए 19 पदकों के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। इन खेलों के दौरान भारत ने पहली बार एथलेटिक्स की ट्रैक स्पर्धाओं में पदक जीतने के अलावा तीरंदाजी में पहली बार स्वर्ण (हरविंदर सिंह के माध्यम से) पदक जीता। स्वदेश लौटने पर पैरालिंपियन खिलाड़ियों को सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है और खेल मंत्री मांडविया ने स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 50 लाख रुपये और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख रुपये का पुरस्कार दिया।

एसडीओ-सीओ के ठिकानों से 22 लाख से ज्यादा नकद व अन्य सामान बरामद
दूसरे दिन की रेड में नई संपत्तियों का खुलासा

शैलेश के गिरिडीह व हजारीबाग आवास से मिले ₹22.08 लाख
मनोज के ठिकानों से जमीन, डुप्लेक्स व कई बैंकों के पासबुक जब्त

PHOTON NEWS RANCHI : गुरुवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने जमीन घोटाला मामले में हजारीबाग एसडीओ शैलेश सिन्हा के हजारीबाग और गिरिडीह ठिकानों से 22 लाख से ज्यादा नगद, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद किया है। दूसरी ओर बड़गाई अंचल के पूर्व सीओ मनोज के ठिकानों से भी कई कागजात जब्त किए हैं। एसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक, शैलेश के पास से 11 जमीन डीड, गिरिडीह आवास से 18 लाख 10 हजार पांच सौ रुपये, हजारबाग आवास से तीन लाख 98 हजार रुपये, 11 मोबाइल, 02 लैपटॉप और एक टैब मिला है। मनोज के यहां से धनबाद जिले की चार डिसमिल जमीन के चार कागजात और छह डिसमिल के कुछ कागजात मिले हैं। रांची में 1.02 करोड़ के डुप्लेक्स के कागजात मिले है। रांची स्थित आवास से कई बैंकों के पासबुक और कुछ मोबाइल जब्त हुए हैं।

सदर थाना में दर्ज मामले को किया था टेकओवर

अप्रैल 2023 में ईडी ने बड़गाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप के आवास से बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी ने पीएमएलए की धाराओं के तहत राज्य सरकार को इससे संबंधित जानकारी दी थी, जिसके बाद रांची डीसी के आदेश पर एक जून 2023 को सदर थाना में कांड संख्या 272/23 दर्ज किया गया था। सदर थाना में दर्ज इस मामले के आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले का नया मामला दर्ज किया था और बड़गाई में 8.86 एकड़ जमीन की धोखाधड़ी की ईसीआईआर दर्ज की थी।

मणिपुर में उपद्रवियों ने स्वास्थ्य केंद्र में लगाई आग, इलाके में तनाव

IMPHAL : मणिपुर के जिरीबाम जिला स्थित बोरोबेक्रा में उपद्रवियों ने बुधवार रात करीब 12.50 बजे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगा दी। घटना पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूर हुई। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना के पीछे कुकी समुदाय के लोगों के शामिल होने की आशंका है। दूसरी तरफ, राजधानी इंफाल में कल पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। इंफाल ईस्ट और वेस्ट में कर्फ्यू जारी है। मैतेई बहुल 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। राज्यपाल एल. आचार्य असम चले गए। उनके पास मणिपुर गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है। इंफाल में 10 सितंबर को सुरक्षाबलों और स्टूडेंट्स में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें करीब 100 स्टूडेंट्स घायल हुए थे। इस प्रदर्शन में इंफाल घाटी के 100 से ज्यादा स्कूल-कॉलेजों के बच्चे शामिल थे।

न्यू रिसर्च जमीन के अंदर प्रदूषण की वजह से जीवों की संख्या में तेजी से आ रही कमी

जलवायु परिवर्तन से भी खतरनाक है प्रदूषित मिट्टी

AGENCY NEW DELHI : जलवायु और प्रदूषण संबंधी एक अद्यतन शोध में यह जानकारी सामने आई भूमि के ऊपर, भूमि उपयोग, जलवायु परिवर्तन और आक्रामक प्रजातियों का जैव विविधता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पहले माना जा रहा था कि यह जमीन के नीचे भी ऐसा ही होगा। लेकिन, ऐसा नहीं है। इसके बजाय शोध से पता चला है कि कीटनाशक और भारी धातु के प्रदूषण ने मिट्टी की जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। जमीन के अंदर रहने वाले जीवों में कमी आने का सबसे बड़ा कारण मिट्टी का प्रदूषण है। इससे पहले माना जाता था कि अंधाधुंध खेती और जलवायु परिवर्तन इस तरह की समस्याओं को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं शोध में हमारी जानकारी को और व्यापक बनाया है। नई जानकारी नए उपाय के को जरूरी बताती है। यह चिंताजनक है कि मिट्टी के प्रदूषण के प्रभावों पर बहुत अधिक शोध नहीं हुआ है। इसलिए इसके प्रभाव जितना हम जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं।

भारी धातु के पॉल्यूशन से मिट्टी की जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान
शोधकर्ताओं की टीम ने 600 से अधिक अध्ययनों के आंकड़ों का किया उपयोग

मिट्टी की सेहत पर इंसानों का असर

आई-साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित इस नए शोध में इस बात को समझने के लिए टीम ने मेटा-विश्लेषण किया। शोधकताओं की टीम ने 600 से अधिक अध्ययनों के आंकड़ों का फिर से उपयोग किया। इसमें हजारों अलग-अलग डेटापॉइंट शामिल थे, ताकि यह देखा जा सके कि दुनिया भर में मिट्टी के स्वास्थ्य पर इंसानों का क्या असर पड़ रहा है। शोध के परिणामों के आधार पर जमीन के ऊपर और नीचे के जीव आम तौर पर एक ही मुद्दे पर बहुत अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं।

जैविक खाद व गीली घास का उपयोग

मिट्टी नमी और पोषक तत्वों को जमा कर सकती है, जो बहुत छोटी अवधि के दौरान जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को बदलावों का सामना करने में मदद कर सकती है। जलवायु परिवर्तन सतह पर अधिक से अधिक प्रजातियों को प्रभावित कर रहा है, इसके जमीन के अंदर प्रभाव अभी सीमित प्रतीत होते हैं। जैविक खाद और गीली घास का उपयोग मिट्टी में अधिक कार्बन के लिए जाना जाता है। यह केंचुओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है।

BRIEF NEWS

टाटा-पटना वंदेभारत एक्सप्रेस सोमवार छोड़कर चलेगी, समय सारिणी जारी

JAMSHEDPUR : रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को टाटा-पटना वंदेभारत एक्सप्रेस की समय सारिणी जारी कर दी। रेलवे से जारी सर्कुलर के मुताबिक, ट्रेन नंबर-20893/20894 टाटा-पटना - टाटा वंदेभारत एक्सप्रेस सोमवार छोड़ कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। सोमवार को टाटानगर में ट्रेन का मेंटेनेंस होगा। इस ट्रेन का मेनटेनेंस होगा। टाटानगर -पटना वंदेभारत 8 कोच की होगी। यह ट्रेन रास्ते में चांडिल, मुरी, बोकारो स्टील सिटी, एनएससीबी गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया में रूकेगी। टाटा-पटना के बीच 495 किलोमीटर की दूरी 7.15 घंटे में तय करेगी। ट्रेन नंबर- 20893 टाटा-पटना एक्सप्रेस सुबह 5.30 बजे टाटानगर से खुलेगी, वहीं 12.45 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन नंबर-20894 पटना-टाटा वंदेभारत एक्सप्रेस दोपहर 2.15 बजे पटना से खुलेगी जो कि रात 9.30 बजे टाटानगर पहुंचेगी।

मेडिकल कॉलेज में आज से होगा नामांकन

DHANBAD : शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सेंट्रल कोटा नीट के तहत 13 सितंबर से दूसरे राउंड का नामांकन शुरू होगा। नीट के तहत मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के 10 सीट पर नामांकन होंगे। पहले राउंड में यहां पांच छात्रों का नामांकन हुआ है। सेंट्रल कोटा के तहत यहां 15 एमबीबीएस की सीट आरक्षित है। स्टेट कोटा के तहत एमबीबीएस की 83 सीट आरक्षित है, जिसमें अभी तक 40 सीटों पर नामांकन हुआ है। 2 सीट सेंट्रल नॉमिनेशन के लिए है। प्राचार्य डॉ. ज्योति रंजन प्रसाद ने बताया कि कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर मुख्यालय, रांची को पत्र लिखा गया है। मेडिकल कॉलेज को जल्द ही कई शिक्षक मिलने वाले हैं।

आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति की बैठक

RANCHI : आरआर स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति की कृष्ण इन में समिति के संरक्षक विक्की यादव के अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक हुई। सर्वप्रथम बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य संरक्षक विक्की यादव ने उपस्थित समिति के पदाधिकारी एवं पूजा समिति के प्रमुख प्रतिनिधियों को पूजा से संबंधित मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश देते हुए आपसी सौहार्द पूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराने की बात कही। मौके पर मुख्य संरक्षक विक्की यादव, अध्यक्ष राहुल यादव, कोषाध्यक्ष रोहित यादव, कार्यकारिणी अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह यादव, मुख्य पुजारी संतोष पाठक, सचिव अजित कुमार, महासचिव धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बबलू सिंह और मनोज अग्रवाल, उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी, सूरज वर्मा, अमित यादव, साहिल यादव, विकास सिंह, सचिन चौधरी, साजन, दीपक वर्मा और राजा, प्रचार मंत्री राजूराय और सुभाष राय, महामंत्री संजीव कुमार, विट्टू चौधरी, शुभम चौधरी और रवि यादव, मंत्री आयुष पाठक और सौरभ, प्रचार मंत्री विद्ध साही और मीडिया प्रभारी आयुष राज वर्मा, राजवीर चौधरी उपस्थित थे।

आदिवासी महिला और उसकी बेटी से मारपीट का है आरोप

पूर्व आजसू नेता ब्रजेश सिंह दोबारा अरेस्ट, फिर रिहा

PHOTON NEWS JSR : पूर्व आजसू नेता ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को पुलिस ने गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार किया, लेकिन वह फिर रिहा हो गया। इससे पहले उसे बुधवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय ने पीआर बांड पर उसी दिन शाम को रिहा कर दिया था। कदमा के भाटिया बस्ती निवासी व कदमा स्थित मंगल सिंह अखाड़ा के संचालक मुन्ना सिंह को पुलिस की एक चूक से जमशेदपुर कोर्ट ने छोड़ दिया था। इस बार पुलिस ने गिरफ्तारी की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। पुलिस ने एक बार फिर मुन्ना सिंह का मेडिकल कराया और उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया। हालांकि सभी धाराओं में 7 साल से कम की सजा होने पर कोर्ट ने एक बार फिर से राहत दे दी। मुन्ना सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष दलील रखी कि मुन्ना सिंह एक समाजसेवी हैं। उन पर बीएनएस और पोक्सो एक्ट की जितनी भी धाराएं लगी हैं, सभी में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। इसी लिए मुन्ना सिंह को जमानत दे दी जाए। घंटों चली बहस के बाद कोर्ट ने मुन्ना सिंह को जमानत दे दी। बुधवार को न्यायालय ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की प्रक्रिया नहीं पूरी करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कदमा थाना को फटकार लगाई और पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

पुलिस गिरफ्त में ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। ● फोटोन न्यूज

बता दें कि ब्रजेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने एक आदिवासी महिला और उसकी बेटी की बेदम पिटाई करने का आरोप है। बीते दिनों पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया इस घटना के बाद कदमा थाना में एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विधायक मंगल कालिंदी समेत कई लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद आजसू ने मुन्ना सिंह को आजसू पार्टी के सारे पदों से हटाते हुए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया था।

क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सर्टिफिकेट कोर्स तक सीमित

DHANBAD : बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के अधीन कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं के पठन-पाठन को लेकर कोई खास प्रबंध नहीं किया गया है। महज चार कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय में भी क्षेत्रीय भाषा खोरठा, कुड़माली और संताली के लिए केवल छह माह का सर्टिफिकेट कोर्स ही कराया जाता है। बीबीएमकेयू में खोरठा, कुडमाली व संताली भाषा के पठन-पाठन की बात करें, तो बीबीएम कॉलेज बलियापुर, चास कॉलेज चास, एसएस कॉलेज चास और माहिंदी बाउरी कॉलेज चंदनकियारी में ही बतौर विषय इनकी पढ़ाई की व्यवस्था है। हाल के दिनों में गोमिया डिग्री कॉलेज को खोरठा विषय का एक शिक्षक दिया गया है, जबकि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा में पढ़ाई कराने का प्रावधान किया गया है। बीबीएमकेयू में क्षेत्रीय भाषाओं के पठन-पाठन के लिए सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जाता है।

तीन बच्चों के साथ मां कुएं में कूदी, सभी की हो गई मौत

PHOTON NEWS LOHARDAGA : लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र अंतर्गत हुदु गांव निवासी फूलदेव मुंडा की पत्नी ऊषा मुंडा (26 वर्ष) ने अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। ऊषा मुंडा अपने तीन बच्चे क्रमशः दिव्या मुंडा (7 वर्ष), शिवम मुंडा (4 वर्ष) व सत्यम मुंडा (1 वर्ष) के साथ कुएं में कूद गई थी, जिससे महिला सहित तीनों बच्चों की मौत हो गई। अब तक आत्महत्या के कारणों का कोई ठोस पता नहीं चला है। मृत महिला के पति फुलदेव मुंडा का कहना है कि उसकी पत्नी गत मंगलवार को मायके नरकोपी थाना क्षेत्र के भैंसादोन गांव जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा गुरुवार की सुबह कुडू थाना क्षेत्र के मकरा घाट दोन स्थित कुआं में शव को देखकर घटना की जानकारी उसे मिली। जिसकी सूचना कैरो व कुडू थाना की पुलिस को भी दी गई। घटना की सूचना के बाद दोनों थानों की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले में लोहरदगा एसपी हारिस बिन जमां का कहना है कि यह घटना कुडू-कैरो के सीमावर्ती क्षेत्र की है।

डायरिया से एक महिला की मौत, चार अस्पताल में भर्ती

CHAKRADHARPUR : डायरिया से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी की स्थिति गंभीर है। गांव के चार लोग अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, सुरबुड़ा गोप टोला निवासी माधो बाडिंग की पत्नी 45 वर्षीय सुमित्रा बाडिंग की मौत हो गई. जबकि 10 वर्षीय बेटी श्रीमती बाडिंग की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गांव के करीब एक दर्जन लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में महिला की डायरिया से मौत की खबर सुनते ही तत्काल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अंशुमन शर्मा ने मेडिकल टीम को गांव रवाना कर दिया। गांव में ही डायरिया पीड़ितों का इलाज शुरू किया गया है। अनुमंडल अस्पताल में सुरबुड़ा गोप टोला की 15 वर्षीय भारती गोप, 8 वर्षीय अर्जुन गोप, 41 वर्षीय रामो गोप तथा 23 वर्षीय अंजली गोप का इलाज चल रहा है।

बांग्लादेशी घुसपैठ की बात पर भाजपा ने साधी चुप्पी : दीपिका

PHOTON NEWS DUMKA : राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार को एक मामले में कोर्ट में पेशी के बाद परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर शोर मचा रही भाजपा ने अचानक चुप्पी क्यों साध ली है। इसके पीछे क्या कारण है, देश के गृहमंत्री अमित शाह को बताना चाहिए। दीपिका ने कहा कि यह भी खुलासा किया जाना चाहिए कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की इतनी आवभगत क्यों की जा रही है। मंत्री ने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावी प्रपंच करके सत्ता हथियाना चाहती है। विदेशी प्लेटफार्म पर राहुल गांधी के बयान को लेकर मचे बवाल पर दीपिका ने कहा कि आखिर राहुल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर क्यों नहीं बोलें। राहुल को लोग सुनते हैं। इंटरनेट के जमाने में अब कुछ भी किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी क्यों न बोलें, उन्हें तो पूरी दुनिया सुनती है। सवालिया अंदाज में कहा कि मणिपुर कांड

पर प्रधानमंत्री आज तक खामोश हैं और आज तक वहां झांकने नहीं गए हैं, तो इससे देश की छवि खराब नहीं हुई है। राहुल गांधी आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आदिवासी हितों की रक्षा का ढोल पीटने वाली भाजपा आखिर झारखंड के आदिवासियों का सरना कोड लागू क्यों नहीं करती है। दीपिका ने कहा कि उनकी सरकार पांच साल पूरा करने जा रही है। विपक्ष के हर साजिश को नाकाम करते हुए हेमंत सरकार राज्यहित में बड़े फैसले कर रही है। इससे विरोधी असहज होकर अनर्गल बयानबाजी के सहारे भ्रम फैलाने में जुटे है।

एनजीटी के किसी आदेश में बस्तियों को तोड़ने की बात नहीं : सरयू

JAMSHEDPUR : विधायक सरयू राय गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संजय कुमार उपाध्याय से नई दिल्ली में मिले। इस दौरान जमशेदपुर की भुइयांडीह स्थित इंद्रानगर-कल्याणनगर बस्ती के करीब 150 घरों को तोड़ने के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा दी गई नोटिस के विविध पहलुओं पर गहराई से विचार किया। सरयू राय ने बताया कि एनजीटी द्वारा इस मामले में जितने भी आदेश विभिन तिथियों पर पारित किए गए हैं, किसी में भी इंद्रानगर-कल्याणनगर बस्ती के घरों को तोड़ने या तोड़ने की नोटिस देने के बारे में निर्देश नहीं दिया गया है। इस मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इसके पहले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त द्वारा पंठनीय शपथ पत्र एनजीटी के समक्ष दायर किया जाना है. झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को भी अपनी निजी शपथ पत्र इस मामले में एनजीटी के सामने दायर करना है।

घाटशिला के गौरीकुंज परिसर, दाहीगोड़ा में याद किए गए साहित्यकार

विभूति भूषण बंदोपाध्याय की 130वीं जयंती पर स्कूली बच्चों ने उकेरे चित्र

PHOTON NEWS GHATSHILA : बांग्ला के महान साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की 130वीं जयंती गुरुवार को घाटशिला के दाहीगोड़ा स्थित गौरीकुंज परिसर में धूमधाम से मनाई गई। गौरीकुंज उन्नयन समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि रवींद्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता के प्रो. सुरंजन ने विभूति बाबू की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसी क्रम में समिति के अध्यक्ष तापस चटर्जी, आईसीसी कंपनी के कार्यपालक निदेशक श्याम सुंदर शेट्टी, सुजान सरकार, काबू दत्ता, डॉ. सुनीता देवदूत सोरेन, आनंद अग्रवाल, शिल्पी सरकार, साधुचरण पाल सहित समिति के तमाम सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर विभूति बाबू के व्यक्तित्व व कृतित्व को याद किया। ज्ञात हो कि घाटशिला क्षेत्र विभूति बाबू की कर्मभूमि थी। उनकी वजह से घाटशिला की ख्याति देश-दुनिया तक पहुंची। उन्होंने यहां कई कहानी व उपन्यास लिखे, जिसमें पाथेर पांचाली सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। गौरीकुंज परिसर में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए।

कार्यक्रम में उपस्थित लोग। ● फोटोन न्यूज

विभूति स्मृति संसद में हुआ हेजैक बाती का मंचन : कॉलेज रोड स्थित विभूति स्मृति संसद परिसर में भी गुरुवार को विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर हेजैक बाती शीर्षक नाटक का मंचन किया गया। इस मौके पर विभूति संस्कृति संसद के अध्यक्ष देवी प्रसाद मुखर्जी, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भकत, ओम प्रकाश सिंह, वीरेंद्र नारायण सिंहदेव, प्रशांत कुमार, काजल डॉन, सुशांतो सीट, मिठु विश्वास, मौसमी सरकार, सत्यजीत सीट किशोरी महतो सहित कई अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रत्न मुखर्जी ने की।

एनएमएल में दो दिनी ब्रांच लेवल बेस्ट वेल्डर प्रतियोगिता आरंभ

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि व अन्य। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS JSR : बमार्माइंस स्थित सीएसआईआर-एनएमएल परिसर में गुरुवार को ब्रांच लेवल बेस्ट वेल्डर प्रतियोगिता आरंभ हुई। सीएसआईआर-एनएमएल एवं भारतीय वेल्डिंग संस्थान (आईआईडब्ल्यू), जमशेदपुर शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि टाटा स्टील के स्पेयर्स सर्विसेज एवं प्रोजेक्ट्स के चीफ कल्याण प्रसाद ने किया। उद्घाटन सत्र में सीएसआईआर-एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधुरी ने स्वागत भाषण में वेल्डिंग के महत्व और उद्योगों में योग्य वेल्डरों की आवश्यकता पर चर्चा की। आईआईडब्लू, जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष डॉ. आनंद प्रभाकरन ने बताया कि इसमें दृश्य और रेडियोग्राफिक, दोनों श्रेणी में विजेता चुने जाएंगे। पांच विजेता राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाएंगे। एनएमएल के प्रधान वैज्ञानिक व अभियांत्रिकी प्रभाग प्रमुख एम. उदय भास्कर राव ने बताया कि एनएमएल में उपलब्ध रोबोट इंटीग्रेटेड एमआईजी वेल्डिंग सुविधा, हाई स्पीड इमेजिंग सिस्टम, स्टीरियो माइक्रोस्कोप के साथ ही को-ऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन और वेल्डिंग सिमुलेटर के बारे में बताया।

गणेशोत्सव में डांडिया नाइट की घूम

PHOTON NEWS JSR : जुगसलाई के एमई स्कूल रोड स्थित संकल्प रेसिडेंसी में सात दिवसीय गणेश उत्सव के अंतर्गत बुधवार को डांडिया नाइट की धूम रही। संगीत, नृत्य और उत्साह से भरी शाम में महिलाएं और उनके पति पारंपरिक गुजराती परिधान में रंगीन रोशनी से जगमगाते आसमान के नीचे डांडिया की लय पर थिरकते रहे। इस उत्सवी माहौल में स्थानीय गायक मोनू शर्मा ने पारंपरिक गीतों की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसने इस शाम को खास बना दिया। ढोल की थाप, डांडिया की टकराहट ने उमंगपूर्ण माहौल बना दिया। प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान ईट एंड रन, सिट एंड ड्रॉ, स्पून एंड मार्बल रेस, नो-फायर कुकिंग कॉन्टेस्ट और पार्टी मेकअप कॉन्टेस्ट जैसी प्रतियोगिता भी हुई।

हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार : जोबा मांझी

कार्यक्रम में भाग लेतीं जोबा मांझी व अन्य। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS CHAKULIA : जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए शहीद होने वाले चाकुलिया के साबुआ हांसदा के 37वें शहादत दिवस समारोह में सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी शामिल हुईं। इस दौरान सांसद ने केरूकोचा ग्राम में साबुआ हांसदा के समाधि स्थल एवं प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हाट मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि राज्य की जनता आने वाले दिनों में फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का मन बना चुकी है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज हर बहन-बेटी को पेंशन और सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा तेजी से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा व जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन, आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार मोहंती, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, पोटका के विधायक संजीव सरदार, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, मोहन कर्मकार, शेख बदरुद्दीन, पवन सिंह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

जुगसलाई से बिष्टुपुर तक हटाए गए ठेले-गुमटी, एसपीजी तैनात

पीएम के स्वागत की तैयारी मुकम्मल

PHOTON NEWS JSR : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आने वाले हैं। वे यहां टाटानगर स्टेशन से झारखंड सहित अन्य राज्यों से खुलने वाली 11 वंदेभारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके स्वागत में टाटानगर स्टेशन के प्लेटफार्म को राष्ट्रीय ध्वज के रंग में सजाया-संवारा गया है।

प्लेटफार्म में पड़ने वाली पटरियों तक की पेंटिंग की गई है। पीएम टाटानगर स्टेशन के बाद बिष्टुपुर में रोड शो, फिर गोपाल मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पीएम के आगमन को लेकर बुधवार से ही एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। एसपीजी लगातार जिला प्रशासन और पुलिस के साथ बैठक कर सुरक्षा से संबंधित जानकारी हासिल कर रही है। इधर, टाटानगर स्टेशन परिसर में सजावट का काम लगातार जारी है। वहीं रोड शो के लिए स्टेशन से लेकर गोपाल मैदान तक सड़क का सुंदरीकरण किया जा रहा है। सड़कों में साफ-सफाई भी युद्ध स्तर पर जारी है। जुगसलाई से बिष्टुपुर जाने वाली सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग भी की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति पीएम के रोड शो के बीच नहीं आ पाए। जुगसलाई से बिष्टुपुर तक सड़क किनारे लगे सभी ठेले-गुमटी हटा दिए गए हैं। पूरी व्यवस्था पर एसपीजी की 40 सदस्यीय टीम भी लगातार नजर बनाए रखे है। कार्यक्रम को लेकर टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 15 सितम्बर को टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1,2 और 3 से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा।

चोर गिरोह के और दो गुर्गे चढ़े पुलिस के हत्थे, चोरी के सामान बरामद

KHUNTI : खूंटी शहर में बंद घरों और दुकानों में ताबड़तोड़ चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के और दो गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गये। गिरफ्तार आरोपितों में खूंटी महादेव टोली निवासी नितिन नायक और अजय नायक शामिल हैं। पुलिस ने दोनों को गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस ने उनके पास से चोरी का टीवी बरामद किया है। यह जानकारी गुरुवार को खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरूण रजक ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि आरोपितों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होने बताया कि पकड़े गये चोर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। नितिन नायक जतन ज्वेलरी, कर्रा और तोरपा रोड चेक नाका के पास बंद घर से चोरी की घटना में शामिल था।

'झामुमो ही कर सकता जल जंगल और जमीन की रक्षा'

लोगों को संबोधित करते विधायक सुखराम उरांव। ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS CHAKRADHARPUR : जल जंगल जमीन की रक्षा अगर कोई कर सकता है, तो वो झामुमो और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही किया जा सकेगा। ये बातें विधायक सुखराम उरांव ने कहीं। उरांव गुरुवार को बंदगाव प्रखंड अंतर्गत कुंदरुगुट भारत सेवाश्रम संघ मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सभा को संबोधित कर रहे थे। विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी-मूलवासी के लिए बहुत जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य कर रही है। इससे जनता को सीधा लाभ पहुंच रहा है। सभा की अध्यक्षता कुंदरुगुटू ग्राम मुंडा शनिका मुंडा के नेतृत्व में 32 गांव के लोग शामिल हुए। इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य, विधायक प्रतिनिधि सह मुखिया मिथुन गागराई, बंदगाव प्रमुख पीटर घनश्याम तियु, क्षेत्र के पीड़ मानकी महता पूर्ति, दिलीप मुंडा, जगदीश बोदरा, पोलुश हामसाय, बिरसा हस्सा, बांगो पूर्ति, बिरसा बोदरा ने भी संबोधित किया, जबकि मंच का संचालन अनुज पूर्ति ने किया।

कुड़मी समाज ने निकाली करम जाऊआ शोभायात्रा

CHAKRADHARPUR : प्रकृति पर्व करमा की शुरूआत हो चुकी है। शहर से लेकर गांव तक करमा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को चक्रधरपुर में कुड़मी समाज द्वारा पोटका के उलीडीह मोड़ से आसनतालिया तक करम जाऊआ लेकर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें चक्रधरपुर के 50 गांव से कुड़मी समाज के लोग पारंपरिक लोकगीत पर नाचते-गाते शामिल हुए। डीजे के साथ-साथ मांदर, ढोल, नगाड़ा बजाते हुए शोभायात्रा गुजर रही थी। समाज के युवा नेता रवि महतो ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी सामाजिक रीतिरिवाज से दूर होती जा रही है। युवाओं में जागरूकता लाने के लिए शोभायात्रा निकाली गई है। शोभायात्रा में भाजपा नेता सह पूर्व विधायक शशि भूषण सामड भी शामिल थे।

BRIEF NEWS

167 लीटर विदेशी शराब के साथ दो कारोबारी अरेस्ट

NAWADA : गुरुवार को नवादा जिले के रजौली थानाक्षेत्र के चितरकोली स्थित समेकित जाँच चौकी से वाहन जांच के दौरान विदेशी शराब के साथ दो कारोबारी की गिरफ्तारी सहित एक यात्री बस को जप्त किया गया है। एसआई उत्पाद संगम कुमार विद्यार्थी ने बताया कि समेकित जाँच चौकी पर हमेशा झारखंड की ओर से आनेवाली हर वाहनों की जाँच की जाती है लेकिन वरीय अधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि यात्री बसों से शराब की तस्करी की जा रही है।

15 जिलों के एसपी समेत 29 आईपीएस का तबादला

PATNA : बिहार पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। गोपालगंज, समस्तीपुर, पूर्णिया समेत 15 जिलों के पुलिस अधीक्षक (एसपी) का तबादला कर दिया गया है। राजधानी पटना के तीनों सिटी एसपी भी बदल दिए गए हैं। गृह विभाग की ओर से भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 29 अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधी अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई।

नवादा में सड़क पर गिरकर अधेड़ की मौत

NAWADA : नवादा नगर के पटना -रांची राष्ट्रीय उच्च पथ पर गुरुवार को नवादा नगर थाने के डाक बाबा के निकट वाहन से उतरने के दौरान एक व्यक्ति सड़क पर गिर गए, जिनके मुंह से खून तथा झाग निकल रहा था । आसपास के लोगों ने मिलकर उस अधेड़ को धर्मशिला अस्पताल पहुंचा दिया,जहां उसकी मौत हो गई । मृतक की तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला गया, जिससे पता चला कि वह व्यक्ति नवादा जिले के नरहट थाने के खनवा गांव के निवासी जीवो सिंह थे। जो अपने वाहन से नवादा आए थे। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई । जिस कारण उनके मुंह से खून तथा झाग निकलने लगा। अस्पताल पहुंचाने के बाद उनकी मौत हो गई । पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का सही-सही पता लगाया जा सकेगा। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया।

13 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

PATNA : बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। शाम सवा 6 बजे तक के लिए चेतावनी जारी हुई है। बिहार के जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है उनमें समस्तीपुर, जमुई, बांका, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शेखपुरा जिला शामिल है। इससे पहले लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय जिले के लिए भी अलर्ट जारी हुआ था। पटना मौसम विज्ञान केन्द्र का कहना है कि अगले दो दिनों तक राज्य में बारिश और वज्रपात की संभावना है। जहां एक ओर शुक्रवार यानी 13 सितंबर को प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होगी, वहीं 14 सितंबर यानी शनिवार को राज्य सभी 38 जिलों में बारिश होने की प्रबल संभावना है।

पुलिस ने नक्सली साजिश को किया नाकाम

पचरुखिया जंगल से तीन किलो के दो आईईडी बरामद

AGENCY AURANGABAD : गुरुवार को औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर नक्सली साजिश को नाकाम कर दिया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया। पुलिस ने अति नक्सल प्रभावित मदनपुर प्रखंड के पचरुखिया के जंगल से तीन-तीन किलो वजन के दो प्रेशर आईईडी बरामद किए हैं।

जंगल से बरामद आईईडी।

बरामदगी से संबंधित जानकारी सदर एसडीपीओ 2 अमित कुमार ने साझा की है। एसडीपीओ ने बताया कि नक्सलियों के गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वप्ना जी मेश्राम के निर्देश पर उनके और केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल (कोबरा-205) वाहिनी के सहायक समादेष्टा विनीत कुमार के नेतृत्व में मदनपुर थाना क्षेत्र के पचरुखिया जंगल और आस-पास के कुछ प्वाईंट को चिन्हित कर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च अभियान के दौरान पचरुखिया एफओबी से दक्षिण-पश्चिम दिशा में जंगल के प्वाईंट पी-11 से दोपहर 12 बजे तीन किलो का प्रेशर आईईडी और फिर कुछ क्षण बाद 12:38 बजे के करीब दूसरा प्रेशर आईईडी बरामद किया गया। बरामद सभी आईईडी को यथास्थान पर ही निष्क्रिय कर धवस्त कर दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद नक्सलियों का मनोबल और गतिविधियां ध्वस्त हुई है। इस कार्रवाई में मदनपुर थाना की पुलिस के साथ-साथ सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। मदनपुर प्रखंड का दक्षिणी इलाका जंगल और पहाड़ों से घिरे होने के कारण भाकपा माओवादी संगठन का सेफ जोन माना जाता था। इस इलाके में नक्सलियों की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस की पहुंच बढ़ती गयी, वैसे-वैसे नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगता गया। पचरुखिया व आसपास के जंगल से लगातार आईईडी बरामद हो रहे है। वैसे भी कहा जाता है कि पचरुखिया या और बांध गोरेया के जंगल में नक्सलियों ने जगह-जगह आईईडी बिछा रखा है। थोड़ी सी चुक किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। यही वजह है कि सर्च अभियान पर रहने वाले सुरक्षा बल एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रखते है। इससे पूर्व में नक्सलियों के बिछाये गये आईईडी की चपेट में कई लोग आ चुके है। हालांकि अब नक्सलियों पर लगाम लगाने में पुलिस बहुत हद तक सफल हुई है।

किसान से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी

BHAGALPUR : घर निर्माण कर रहे जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जमनी गांव निवासी सह राजद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता से अपराधियों ने 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी है। अपराधी बिजल पासवान, संजय पासवान, लालू पासवान, चंदन पासवान, पंचा पासवान और अजय पासवान ने शंकर प्रसाद गुप्ता से रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मार देने का धमकी दिया है। जिसको लेकर शंकर प्रसाद गुप्ता ने गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर आवेदन दिया है। शंकर गुप्ता ने कहा कि उक्त लोगों के द्वारा मुझे कई बार फोन के माध्यम से जान के मरने की धमकी दी गई थी। जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। इन अपराधियों के द्वारा जमनी गांव में गांजा और देसी शराब बेचा जाता है। जिस वजह से उनके पास असामाजिक तत्व के लोगों का आना-जाना लगा रहता है। मैंने इन सब के बचाव के लिए अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था।

सारण में मुख्यमंत्री ने दी कई योजनाओं की सौगात

छात्रावास का उद्घाटन करते सीएम नीतीश कुमार।

AGENCY SARAN : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रख्यात समाजवादी और जननायक नेता कपूर्री ठाकुर के साथ अपनी तस्वीर देखकर मुस्कराने लगे। दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलेवासियों को कई योजनाओं की सौगात देने सारण पहुंचे थे।

उनका कार्यक्रम मढ़ौरा और अमनौर के अपहर में था। उन्होंने मढ़ौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में नवनिर्मित 300-300 क्षमता के 2 छात्रावासों और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आज मढ़ौरा में सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस रही। वहीं मुख्यमंत्री का काफिला अमनौर पहुंचा। उन्होंने वहां के अमृत सरोवर का अवलोकन किया और वहां पर पौधरोपण भी किया। वहीं मढ़ौरा पहुंचने पर सारण के जिला अधिकारी अमन समीर के द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेट किया गया। यहां भी सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री आज सारण मैं एक से डेढ़ घंटे की अवधि में रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विकास के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, छपरा विधायक डॉ सीएन गुप्ता मौजूद थे।

मोतिहारी में दिखा तेंदुआ, दहशत में ग्रामीण, तलाश में जुटा वन विभाग

AGENCY MOTIHARI : बिहार के मोतिहारी में खूंखार का डर लोगों को सता रहा है। जिले के संग्रामपुर प्रखंड के मधुबनी पंचायत में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना मिलने के बाद से मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए के पगमार्ग से उसकी तलाश में जुट गई है। डर के मारे ग्रामीण घरों से बाहर निकलने को तौयार नहीं हैं, वो रातभर लाठी-डंडा लेकर जाग रहे हैं।

बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर आई वन विभाग की टीम को अभी तक तेंदुआ नजर नहीं आया है। वहीं घास पर पगमार्क होने के कारण जानवर की पहचान नहीं हो पा रही है। हालांकि ग्रामीणों को आशंका है कि तेंदुआ गांव में ही कहीं छुपा है। मिली जानकारी के अनुसार पहली बार मंगलवार की रात मधुबनी पंचायत के वार्ड नंबर तीन के दरियापुर गांव के रहने वाले मोनाफ खान के बरामदे पर तेंदुए को देखा गया था। मोनाफ खान के घर के बाहर तेंदुए को देख लोग दहशत में आ गए। वहीं घरवालों ने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया और शोर मचाने लगे। एक ग्रामीण ने बताया कि करीब रात के 10 से 11 बजे पास की बांस की झाड़ियों में लोगों ने तेंदुए को देखा था। ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर उसे भगाने की कोशिश भी की। लेकिन वो वहीं छुप गया। उसके बाद सुबह जब हम लोगों ने देखा तो वो वहां पर नहीं था। बुधवार को भी एक ग्रामीण महिला ने तेंदुए के देखे जाने का दावा किया, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। मोतिहारी वन प्रमंडल के डीएफओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों ने एक तस्वीर भेजी है, जो धुंधली है। उस तस्वीर में जानवर की पहचान नहीं हो पा रही है।

छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर किया हमला

JAMUI : बिहार सरकार ने बालू खनन पर फिलहाल रोक लगा रखी है। इसके बावजूद बालू माफिया आए दिन अवैध तरीके से खनन करते नजर आते हैं। इस बार बालू माफियाओं ने कार्रवाई करने आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। जमुई एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि जिले के बरहट थानान्तर्गत गुगुलडीह इलाके में घटना को अंजाम दिया गया है। बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय बालू माफियाओं और अन्य ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया। जिसकी सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए बरहट थानाध्यक्ष द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिद्धौर और सदर अस्पताल ले जाया गया है। बालू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई में गिद्धौर थाना पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार और 3 सिपाही घायल हुए हैं।

नर्स ने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काटा क्लीनिक में कर रहा था रेप की कोशिश

AGENCY SAMASTIPUR : बिहार के समस्तीपुर में एक डॉक्टर ने अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर एक नर्स के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के मुताबिक डॉक्टर शराब के नशे में धुत था। क्लीनिक में उसके साथ ज्यादती होती उससे पहले ही उसने डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट, क्लीनिक में रखे ब्लेड से, काट दिया और जान बचाकर बाहर निकल गई। डॉक्टर के दो सहयोगी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन वह एक मकई के खेत में जाकर छिप गई।

यह मामला मुसरीघरारी थाना इलाके के फिजियोथेरेपी नर्सिंग होम के डॉक्टर की क्लीनिक का है। डीएसपी संजय कुमार पांडेय ने वारदात के शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शराब में धुत डॉक्टर और उसके दो सहयोगी नर्स के साथ जबरदस्ती की कोशिश कर रहे थे। विरोध में नर्स ने आरोपी डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट ब्लेड से काट दिया और जान बचाकर भागी और बाहर निकलकर खेत के अंदर छिपकर 'डायल 112' को कॉल करके बुलाया। पीड़ित नर्स ने बताया कि घटना के वक्त डॉक्टर ने क्लीनिक में लगे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया था। क्लीनिक को अंदर से लॉक कर दिया और तीनों टूट पड़े। जान बचाने के लिए उसने ब्लेड से आरोपी का प्राइवेट पार्ट काट दिया और क्लीनिक का ताला खोलकर फरार हो गई। मकई के खेत में जाकर डायल 112 को बुलाया। इधर आवेदन के आधार पर मुसरीघरारी थाने में मामला दर्ज कराया है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी डॉक्टर तेघरा का रहने वाला है जबकि दोनों सहयोगी समस्तीपुर के ही रहने वाले हैं। तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

ईडी का छापा, 90 लाख कैश और चांदी की ईंटें बरामद

AGENCY PATNA : बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बड़ी कामयाबी मिली है। इस केस में हालिया छापेमारी के दौरान 90 लाख रुपये कैश और 13 किलोग्राम चांदी की ईंटें जब्त की गईं। ईडी के आधिकारिक सूत्रों से यह जानकारी मिली है।

बता दें कि ईडी ने इसी हफ्ते दिल्ली के दो ठिकानों के अलावा कोलकाता और मुंबई में कुछ जगहों पर छापेमारी की थी। सूत्रों ने बताया कि बिहार ऊर्जा निगम में प्रधान सचिव रह चुके 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस के कुछ कथित पुराने सहयोगियों के ठिकानों पर दो दिनों तक छापे

- गुलाब यादव और संजीव हंस केस में मिली बड़ी कामयाबी

गुलाब यादव संजीव हंस

मारे गए। ताजा छापेमारी में करीब 90 लाख रुपये नकद और 13 किलोग्राम चांदी जब्त की गई। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में पहली बार जुलाई में छापा मारा था। उस समय ईडी द्वारा एक दर्जन से अधिक महंगी घड़ियां, लगभग एक किलोग्राम सोने के आभूषण और कुछ निवेश संबंधी कागजात जब्त किए गए थे। इसके बाद बिहार सरकार द्वारा उन्हें प्रधान सचिव के पद से हटा दिया गया था।

भ्रष्टाचार में संलिप्त है डबल इंजन की सरकार : तेजस्वी

AGENCY DARBHANGA : बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता जन संवाद यात्रा के क्रम में तीसरे दिन दरभंगा पहुंचकर प्रेक्षागृह में पांच विधानसभा के कार्यकताओं के साथ बैठक की। बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार 20 साल से लगातार विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया है। वहीं तेजस्वी ने बिहार के

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से वो उपमुख्यमंत्री बने हैं, एक काम बता दें, जो उनके द्वारा किया गया हो। सिर्फ गाड़ी और सिक्योरिटी लेकर जनता के पैसे से घूमते हैं। घूमना कोई काम है क्या? हम से ज्यादा जनता के बीच में रहे हैं? रात दिन हमलोगों ने सड़कों पर बिताए हैं। क्या वो हम से ज्यादा जनसभा किए हैं? ये लोग बेकार की बाते कर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं।घुटने में जिसका दिमाग है, उसके बारे में क्या कहेंगे। वहीं उन्होंने मिथिलांचल के चुनावी नतीजे पर कहा कि ठीक है नतीजे हमारे हिसाब से नहीं आए, लेकिन हम कमजोर नहीं है। बिहार में सबकी लड़ाई हमसे ही होती है। वहीं उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में लगी हुई है। अभी जो बिहार में सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले बार तो सरकार लगभग बना लिए होते, अगर बेईमानी नहीं होती। बता दें कि केंद्र सरकार ने आम बजट में बिहार को विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष पैकेज देने की घोषणा की है।

चारा घोटाले की उपज हैं तेजस्वी : बिजेंद्र यादव

AGENCY PATNA : बिहार की सियासत में इन दिनों जुबानी जंग का दौर जारी है। आरजेडी कई मुद्दों को लेकर लगातार सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है तो जेडीयू के नेता भी आरजेडी पर पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी के बाद ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी को कोई ज्ञान नहीं है। तेजस्वी यादव पर तीखा हमला करते हुए बिजेंद्र प्रसाद यादव ने उन्हें चारे घोटाले की उपज बताया। बिजेंद्र यादव ने कहा कि जब तेजस्वी पैदा हुए थे, बिहार पहला राज्य है जहां खजाने से ही पैसे की लूट हो गयी थी। आज

तक इतिहास नहीं है दुनिया में कहीं। बिहार में अपराध बढ़ने के विपक्ष के आरोप पर बिजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। समाज में राम हैं तो रावण भी है। कृष्ण हैं तो कंस भी है। इसीलिए तो कानून बना है। बिजेंद्र यादव ने नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा को बकवास बताया।

अब दवाइयों के लिए इधर-उधर भटकने की नहीं होगी जरूरत

बिहार के 27 जिलों में खुलेंगे औषधि भंडार केंद्र

AGENCY PATNA : बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और अन्य अस्पतालों को समय पर दवा उपलब्ध हो इसके लिए 27 जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। बिहार सरकार द्वारा इस योजना को स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पहले चरण में बीस जिलों में औषधि भंडार केंद्र बनाए जाएंगे। बता दें कि एक औषधि भंडार केंद्र के निर्माण पर 85 लाख रुपए खर्च होंगे। इन औषधि केंद्रों का निर्माण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए आवंटित राशि से किया जाएगा। अभी इस योजना मद में कुल 17 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। बता दें कि यह

औषधि भंडार केंद्र सदर अस्पताल या सिविल सर्जन कार्यालय में बनाने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि सदर अस्पताल या सिविल सर्जन कार्यालय में कम से कम आठ हजार वर्ग फीट जगह चिह्नित कर विभाग को इसकी जानकारी अविलंब दें। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अस्पतालों को कुछ जिलों में स्थापित औषधि भंडार केंद्र और अधिकतर दवाओं की आपूर्ति बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम से की जाती है।

राजद सुप्रीमो लालू यादव की हुई एंजियोप्लास्टी

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एंजियोप्लास्टी हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को हार्ट में दिक्कत के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। 76 साल के लालू को दो दिन पहले मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि हार्ट में ब्लोकेज की समस्या के चलते डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी की सलाह दी। हालांकि, अभी तक अस्पताल की ओर से लालू का हेल्थ अपडेट जारी नहीं हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एंजियोप्लास्टी के बाद लालू यादव की हालत स्थिर है। उन्हें एक या दो दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या

CHAMPARAN : बिहार के बगहा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। रामनगर थाना क्षेत्र के चुड़िहरवा गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसके पटीदारों पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक महिला घर में सो रही थी। इसी दौरान देर रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब महिला के जेठ के बेटों ने आकर गोली मार दी। महिला के पुत्री ने बताया कि रास्ते को लेकर पटीदारों से विवाद चल रहा था। इसी क्रम में पंचायती के दौरान विवाद को सुलझा लिया गया था। मृतका की शिनाख्त सुनरपति देवी के रूप में हुई है। उसके पति का नाम सरयु राय है। आरोप है कि सरयु के भाई संजय राय के बेटे ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।

विस चुनाव से पूर्व जदयू ने की प्रकोष्ठों में नए अध्यक्ष व प्रभारियों की नियुक्ति

AGENCY PATNA : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार के सभी राजनीतिक दल सक्रिय होने लगे है। जदयू ने प्रदेश की नई टीम के गठन के बाद अब विभिन्न प्रकोष्ठों में नए अध्यक्ष और प्रभारी की नियुक्ति की है। जदयू ने राज्य की सभी 243 सीटों के लिए विधानसभा प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में गुरुवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पत्र जारी कर दिया है।

जारी पत्र के अनुसार भारती मेहता को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है,जबकि पूर्व मंत्री डॉ। रंजू गीता प्रभारी के तौर पर काम देखेंगी। साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होने लगी है। सभी दल विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे-धीरे एक्टिव

मोड में आते जा रहे हैं। एक तरफ जहां आरजेडी ने कार्यकताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है तो वहीं जेडीयू भी चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई है। पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मनीष कुमार को युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि वशिष्ठ सिंह को प्रभारी बनाया गया है। राधेश्याम को छात्र जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव को छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया गया है, जबकि मेजर इकबाल हैदर प्रभारी होंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की तरफ से जारी लिस्ट में राजेश त्यागी को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है।पूर्व विधायक अरुण मांझी इसके प्रभारी होंगे।सुरेंद्र उरांव को अनुसूचित जनजाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज कुमार को किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है । वहीं डॉक्टर एनल बी सिंह चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। धनजी प्रसाद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जबकि विधान पार्षद ललन सर्राफ को प्रभारी का दायित्व दिया गया है। राम चरित्र प्रसाद को तकनीकी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील कुमार को शिक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, जबकि नीतीश पटेल को मीडिया प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है।

'अपराजिता' बनने के लिए पहले घरों और कार्यस्थलों को बनाना होगा सुरक्षित

हर जघन्य यौन अपराध के बाद सजा-ए-मौत का शोर उठना और अध्यादेश जारी करके या विधेयक पारित करके इसे मान लेना काफी आम हो गया है। दिल्ली में एक महिला से वहशियाना दुष्कर्म के बाद 2013 में आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों ने यौन हमले के लिए बढ़ी हुई सजा की खातिर संशोधन किए। अब पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक 2024 में यौन अपराधों के लिए दंड बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। विधेयक में बलात्कार के विशिष्ट मामलों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड और त्वरित जांच जैसे कड़े उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। यह किसी बड़ी आपराधिक घटना के बाद जन आक्रोश पर पश्चिम बंगाल की विधायी प्रतिक्रिया को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य कानूनी ढांचे को मजबूत करना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। विधेयक में दुष्कर्म पीड़िता की मृत्यु होने अथवा मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है,जिससे निवारक प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यौन अपराधों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी की जाए,जिसका उद्देश्य न्याय में तेजी लाना है। विधेयक पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा को मजबूत करता है तथा खुलासा करने पर 3-5 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है। विधेयक में यौन हिंसा के मामलों के लिए समर्पित विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। विधेयक नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े मामलों को लक्षित करता है, कठोर दंड और बढ़ी हुई निगरानी लागू करता है। विधेयक पुनर्वास और सामाजिक सुधारों के बजाय दंडात्मक कार्रवाइयों को अधिक प्राथमिकता देता है तथा गहन प्रणालीगत मुद्दों की उपेक्षा करता है। कठोर दंड के बावजूद यौन अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो विशुद्ध दंडात्मक कानूनों के सीमित प्रभाव को दर्शाता है। विशेष न्यायलयों की स्थापना से मौजूदा न्यायिक ढांचे पर दबाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से प्रक्रियागत देरी हो सकती है। निर्भया के बाद शुरू किए गए फास्ट-ट्रैक कोर्ट को भी बोझिल कानूनी व्यवस्था और संसाधनों की कमी के कारण इसी तरह की देरी का सामना करना पड़ा। निवारक के रूप में मृत्युदंड के उपयोग पर व्यापक रूप से बहस हुई है, परंतु इसकी प्रभावशीलता के साक्ष्य सीमित हैं। वर्मा समिति की रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मृत्युदंड से यौन अपराधों में पर्याप्त कमी नहीं आती है, इसलिए अधिक प्रभावी समाधानों की आवश्यकता है। यह विधेयक केंद्रीय कानून के साथ संभावित संघर्ष उत्पन्न करता है, जिससे कानूनी चुनौतियों के कारण कार्यान्वयन में देरी होने की संभावना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार ऐसे संशोधनों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जिससे कानून का लागू होना जटिल हो जाता है। विधेयक यौन हिंसा पर शिक्षा या जनजागरूकता अभियान जैसे निवारक उपायों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम जागरूकता और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो ऐसे अपराधों को कम करने के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पीड़ितों के लिए सशक्त पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रणालियां शुरू करना दंडात्मक उपायों का पूरक होगा। यौन अपराध के मामलों से निपटने में होने वाली देरी को कम करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे को अधिक संसाधन आवंटित करना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य न्यायपालिका को डिजिटल बनाना है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके। स्कूली बच्चों और आम जनता को लक्षित करके जागरूकता अभियान चलाकर यौन हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करते हुए इस तरह की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। सखी वन स्टॉप सेंटर पहल शिक्षा और जागरूकता प्रदान करती है, जिससे महिलाओं को अपराधों की जल्द रिपोर्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य के कानूनों का, केंद्रीय ढांचे के साथ सामंजस्य होने से सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है और अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सकता है। केरल में राज्य की पहलों के साथ पोक्सो का सफल संरेखण, एक सहयोगी दृष्टिकोण के लाभों को दर्शाता है। स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और लिंग संवेदीकरण जैसे दीर्घकालिक निवारक उपायों को शुरू करने से यौन हिंसा को रोकने में मदद मिल सकती है। दिल्ली पुलिस निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अपराजिता विधेयक पश्चिम बंगाल में यौन हिंसा को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सार्वजनिक आक्रोश के प्रति विधायी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। हालांकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो दंडात्मक उपायों को पुनर्वास, सार्वजनिक जागरूकता और बुनियादी ढांचे के समर्थन के साथ जोड़ता है। राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वित प्रयास, महिलाओं और बच्चों के लिए स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन और उन्नत सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि मौत की सजा देने से यौन अपराध थम जाते हैं, लेकिन ऐसे अपराधों के बाद ज्यादा कठोर कानूनों की मांग पर अक्सर एक आधिकारिक प्रतिक्रिया होती है। यह कहकर कि बलात्कार मानवता के लिए अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की जरूरत है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हर सरकार की है कि कानून प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं और यौन हमलों को रोकने व दंडित करने के लिए पुलिस बिना पक्षपात काम करे। अगर महिलाओं के लिए पहले घरों व कार्यस्थलों को महफूज बनाकर उनके आगे बढ़ने की राह से अवरोध हटाए जाएं, तो इंसाफ और अच्छे से दिया जा सकेगा।

ANALYSIS

जीवन का करें वरण

गिरीश्वर मिश्र

औद्योगीकरण तथा नगरीकरण आदि ने समाज में विद्यमान एकीकरण या जोड़ने की क्षमता को लगातार कम किया है। अब व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति की निजी इच्छाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। समाज द्वारा नियमन और निगरानी अनावश्यक दखल मानी जा रही है। इन सबके बीच आदमी की बुद्धि, भावना और सामाजिकता सबके बीच संतुलन बिगड़ता जा रहा है। लोगों के आपसी रिश्ते बेतरतीब हो रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक संरचना में बदलाव और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ लोग कर्ज शेयर बाजार में गिरावट और गलाकाट व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता जैसी मुश्किलों में उलझते जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर नकारात्मक जीवन की घटनाएं आदमी में विषाद, निराशा और खुद के बारे में नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही हैं।

वैसे तो आत्महत्या जैसी घटनाओं का विभिन्न संस्कृतियों में लंबा इतिहास है, फिर भी समकालीन समाज में जिस तेजी से ये लगातार बढ़ रही हैं, वह पूरे विश्व के लिए चिंता का बड़ा कारण है। आत्महत्या की दिशा में आगे बढ़ना और उसे अंजाम देना बड़ा जटिल व्यवहार है। यह आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में आ रहे तीव्र परिवर्तन के दबावों से जुड़ा हुआ है। भारत के संदर्भ में आधुनिकीकरण, धर्म की जगह सेकुलर दृष्टि को तरजीह और संयुक्त परिवार का नष्ट होना कुछ ऐसी घटनाए हैं,जो हमारी सोच को उलट-पलट रहे हैं और व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार को नियंत्रित संयोजित करने की प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं। औद्योगीकरण तथा नगरीकरण आदि ने समाज में विद्यमान एकीकरण या जोड़ने की क्षमता को लगातार कम किया है। अब व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति की निजी इच्छाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। समाज द्वारा नियमन और निगरानी अनावश्यक दखल मानी जा रही है। इन सबके बीच आदमी की बुद्धि, भावना और सामाजिकता सबके बीच संतुलन बिगड़ता जा रहा है। लोगों के आपसी रिश्ते बेतरतीब हो रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक संरचना में बदलाव और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के साथ लोग कर्ज शेयर बाजार में गिरावट और गलाकाट व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता जैसी मुश्किलों में उलझते जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर नकारात्मक जीवन की घटनाएं आदमी में विषाद, निराशा और खुद के बारे में नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रही हैं। इन सबके बीच आदमी सारे कष्टों से मुक्ति के उपाय के रूप आत्महत्या के विचार की ओर आकृष्ट होता है। वह खुद अपने आप से और अपनी दुनिया से पलायन करने को उद्यत होता है। बढ़ते भावनात्मक तनाव के बीच मृत्यु का आकर्षण तीव्र हो उठता है। भावनात्मक कठिनाइयों से लड़ते हुए आदमी का आत्मनियंत्रण टूटने लगता है। अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कुछ देशों में आयु के साथ आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कुछ देशों में मध्य आयु वर्ग में इसकी प्रवृत्ति सर्वाधिक है, तो कुछ में किशोरवय में यह अधिक है। आज आत्मघात करने की मानसिक अवस्था वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या का रूप ले रही है। एक अनुमान के अनुसार, विश्व में होने वाले आत्महत्या के कुल मामलों के 78 प्रतिशत निम्न और मध्यम आय वाले देशों से आते हैं। मनुष्यों की मृत्यु के कारणों में पंद्रहवां आत्महत्या का है। पूरे विश्व में लगभग सात लाख से अधिक लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है। प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 10.7 आत्महत्या की दर का अनुमान किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15-44 वर्ष के आयु वर्ग में आत्महत्या, मृत्यु के तीन प्रमुख कारणों में शुमार है। यद्यपि पुलिस के आंकड़े अपर्याप्त हैं और राष्ट्रीय अपराध रिकर्ड ब्यूरो के प्रदत्त संकलन की विधि भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, तथापि उनसे पता चलता है कि 25-34 आयु वर्ग में और बुजुर्गों में आत्महत्या के मामले अधिक थे। इसी तरह पुरुषों, खंडित परिवारों, तलाकशुदा लोगों में, अकुशल कामगारों में, निम्न सामाजिक और आर्थिक समुदायों के लोगों में, नकारात्मक जीवन की परिस्थितियों (जैसे- पारिवारिक कलह, वैवाहिक समस्या) से जूझते लोगों में इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं। आत्महत्या को सीमांत व्यक्तित्व विकृति का एक लक्षण माना गया है। कई मामलों में इसका संबंध मादक द्रव्य और पदार्थों के सेवन से भी जुड़ा पाया जाता है। इसे खानपान, चिंता, अवसाद, द्विछोरी (बाई पोलर) विकृति तथा त्रासदी उपरांत विकृति (पीटीएसडी) से भी जुड़ा पाया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खाइम ने समाज और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया था। इसे फ्रायड के विचारों को ध्यान में रखकर आत्महत्या को दूसरे व्यक्ति की हत्या का विलोम और दूसरे के प्रति क्रोध की आत्माभिमुख अभिव्यक्ति भी कहा गया है। इसकी व्याख्या मृत्यु की मूल प्रवृत्ति तथा हत्या करने की आकांक्षा और मृत्यु की इच्छा आदि से भी जोड़ कर की जाती है। इसे मनोपीड़ा (साइकिक) से भी संबंधित किया गया है, जो असह्य हो और जीना दूभर कर दे। उतावलापन और कार्य में चरमोत्कृष्टता (परफेक्शन) की प्रवृत्ति से भी यह जुड़ी होती है। ध्यातव्य है कि आत्महत्या स्वयं अपने द्वारा अपने को खत्म करने के लिए आरंभ किया गया सचेत व्यवहार है। वस्तुतः यह अस्वास्थ्य की एक बहुआयामी अवस्था है, जब कोई व्यक्ति किसी मुद्दे के समाधान के रूप में आत्महत्या का विकल्प तय करता है। उसे और दूसरे रास्ते बंद लगते हैं और यही उसे सर्वथा उचित उपाय लगने लगता है। अक्सर आत्महत्या के अंतिम कदम उठाने के पहले व्यक्ति कई व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो इस (आगामी) दुर्घटना का संकेत देते हैं। स्वैच्छिक आत्महानि या खुद को नुकसान पहुंचाने का व्यवहार भी कई तरह का होता है। जहर खाना, कोई गलत या अधिक मात्रा की दवा या पेस्टीसाइड आदि खाना, फांसी लगाना, नस काट कर, पानी में कूद कर, पिस्टल आदि घातक हथियार से खुद को अपने को आहत करते हैं और जान दे देते हैं। खुद को आघात पहुंचाने की प्रवृत्ति आत्महत्या की दिशा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति की सहयोगी होती है। इन सबमें जोखिम को बढ़ाने वाले कारक एक से हैं। गैर घातक आत्मघाती व्यवहार भी किया जाता है, जिसको पहचानना सरल नहीं होता है। उसे समझने के लिए व्यवहार की तीव्रता और व्यवहार कितना प्राणघाती है, इन सब पर गौर करना जरूरी होता है। इस तरह के लक्षणों वाले रोगियों को संभालने के लिए प्रभावी मनोचिकित्सा की जरूरत होती है। ऐसे रोगियों की जांच और मूल्यांकन अच्छी तरह से होना चाहिए। मूल्यांकन के आधार पर औषधि या गैर औषधि वाले उपायों की सहायता ली जा सकती है। खासतौर पर आत्मघात के लक्षणों वाले रोगियों के जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष किस्म के उपचार की जरूरत पड़ती है। आत्महत्या की सोच को जांचने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रश्नावलियों का भी विकास किया है, जिससे उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है। ऐसे रोगी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी अच्छी तरह देख-रेख और निगरानी जरूरी है। सामाजिक रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के लिए समस्या-समाधान, थिरैपी (जैसे- संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या सीबीटी) और परामर्श उपयोगी हैं। इस परिस्थिति के लिए प्राथमिक रोकथाम की कोशिश करते हुए समाज के स्तर पर जोखिम को घटाना आवश्यक है। इस दृष्टि से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, तनाव, वैवाहिक संघर्ष, मादक द्रव्य सेवन, हथियारों की उपलब्धता आदि को कम करना होगा। द्वितीयक रोकथाम के अंतर्गत इसके जोखिम वाले लोगों को पहचानना और उचित तथा सामयिक हस्तक्षेप जरूरी है। समय पर हस्तक्षेप करना बड़ा लाभकर होता है। क्राइसिस हेल्पलाइन और परामर्श की प्रभावी सेवा उपलब्ध कराना जरूरी है। तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत जो लोग आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं और जीवित हैं, उनको शर्म और ग्लानि से मुक्त करना और पुनर्वास का प्रयास शामिल है। आत्महत्या के प्रश्न को समाज में हम किस नजरिए से देखते हैं, यह महतवपूर्ण है। इसे लेकर चुप्पी तोड़ने की आवश्यकता है। खुले मन से, समझदारी की दृष्टि से सहायता की ईमानदार कोशिश से उन लोगों को बचाया जा सकेगा, जो इस घातक मनोरोग से ग्रस्त हैं और जिन्हें मदद की आवश्यकता है। इसके लिए जन-जागृति और सहयोग की संस्कृति विकसित करनी होगी। इस तरह के विचार-विमर्श से संबंधित नीतियों का निर्माण और कायदे-कानून बनाने में सहायता मिलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार आख्यान में बदलाव लाने के लिए कहा है। इसका आशय यह भी है कि मानसिक स्वास्थ्य को वरीयता मिले, उसके लिए आवश्यक सुविधा तक जन सामान्य की पहुंच सुनिश्चित हो। आत्महत्या को रोकना असंभव नहीं है। इसके लिए उचित समय पर इस दिशा में आगे जा रहे व्यक्ति से मिल रही चेतावनी के संकेत को समझ कर उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके लिए आत्महत्या को लेकर समाज में व्याप्त आख्यान को नए सिरे से गढ़ना होगा।

पंजाब और हरियाणा में गहराता जल संकट

पंजाब और हरियाणा में धान की खेती भारत की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु जल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण यह असंधारणीय होती जा रही है। धान की खेती के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन होने से इस क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। हरियाणा में 88 जल इकाइयों को अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में रखा गया है। इस समस्या से निपटने के लिए कृषि और जल संसाधन दोनों की सुरक्षा के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है। भूजल का अत्यधिक दोहन : पंजाब और हरियाणा में धान की खेती के लिए अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे भूजल स्तर में भारी कमी आई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2023 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि धान की खेती के लिए अत्यधिक जल दोहन के कारण पंजाब के 87% ब्लॉकों का अति दोहन किया गया। धान की खेती में प्रति किलो चावल के लिए लगभग 4000-5000 लीटर जल की खपत होती है, जिससे क्षेत्र के जल संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसकी तुलना में बाजरे को प्रति किलो केवल 500 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जो जल की आवश्यकताओं में भारी अंतर और धान की खेती की असंधारणीय प्रकृति को दर्शाता है। ट्यूबवेल के लिए दी जाने वाली मुफ्त बिजली ने भूजल के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा दिया है, जिससे यह संकट और भी बढ़ गया है। पंजाब के किसानों को वर्ष 2023-24 में बिजली,नहर के पानी और उर्वरक के लिए 38973 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी मिली, जिससे भूजल का निरंतर अतिदोहन हो रहा है। धान की खेती के कारण बढ़ता जल तनाव, जलवायु परिवर्तन के कारण और भी अधिक हो गया है। अनियमित वर्षा के कारण जलभृतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट से कृषि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को खतरा

है। धान की खेती एकल फसल प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिससे जैव विविधता कम होती है और मृदा के पोषक तत्व कम होते हैं, जिससे कृषि संधारणीयता में कमी आती है। अध्ययनों के अनुसार फसल चक्रण से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है, परंतु धान की खेती ऐसी विविधता को हतोत्साहित करती है। जल की अधिक मांग के कारण रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी बढ़ जाता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है तथा जलस्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। बाढ़ सिंचाई धान की खेती में प्रयुक्त होने वाली एक प्रमुख विधि है, जिससे वाष्पीकरण और अपवाह के माध्यम से जल की बहुत बबार्दी होती है। निरंतर धान की खेती से मृदा लवणता बढ़ जाती है, जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और यह अन्य फसलों के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। धान के खेत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेष रूप से मीथेन के उत्सर्जन में जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है और दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता को प्रभावित करता है। धान की खेती प्रति हेक्टेयर 5 टन कार्बो डी-ऑक्साइड समतुल्य हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, जो इसे कृषि उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाती है। दालों, तिलहनों और बाजरा जैसी कम जल की खपत वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने से जल का उपयोग काफी कम हो सकता है और संधारणीयता में सुधार हो सकता है। पंजाब की 2024 की योजना, धान को छोड़कर वैकल्पिक फसलों को उगाने के लिए 17500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन की पेशकश करती है, जिसका उद्देश्य विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए धान से अन्य संधारणीय फसलों पर सब्सिडी को पुनर्निर्देशित करना आवश्यक है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देने से पैदावार को बनाए रखते हुए जल संरक्षण में मदद मिल सकती है। एमएसपी और खरीद कार्यक्रमों के माध्यम से दालों और तिलहन जैसी फसलों के लिए बाजार आश्वासन सुनिश्चित करने से किसानों के धान के अलावा अन्य फसलों को उगाने का डर कम हो सकता है। भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 2023 में पंजाब का 92.5% चावल खरीदा, इसी तरह के तंत्र वैकल्पिक फसलों को उगाने की प्रथा को बढ़ावा दे सकते हैं। फसल विविधीकरण और जल-बचत प्रथाओं के लाभों के संबंध में किसानों को शिक्षित करने से दीर्घकालिक परिवर्तन को बढ़ावा मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित प्रयास, पुनर्गठित सब्सिडी, जल-कुशल प्रथाओं और बाजार आश्वासन पर ध्यान केंद्रित करके पंजाब और हरियाणा को सतत कृषि की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इस तरह के सुधार कृषि उत्पादकता को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करेंगे। क्षेत्र के जल संसाधनों को सुरक्षित करेंगे और कृषक समुदायों के भविष्य को सुनिश्चित करेंगे।

Social Media Corner

सच के हक में...

मध्य प्रदेश में सेना के दो जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है - और, महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक। अपराधियों की ये निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हों और गंभीरता से विचार करें - देश की आधी आबादी की रक्षा की ज़िम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे!

(राहुल गांधी का 'एक्स' पर पोस्ट)

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के महासचिव और वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी जी के निधन का समाचार सुनकर गहरा दुःख हुआ। उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। वे एक कुशल राजनेता, विचारक और जनता के हितों के लिए समर्पित नेता थे। मरांग बुरु से दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं।

(सीएम हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में घट रही इंसानी अभिरुचि

वन संपदा हमारे जीवन के लिए कुदरती उपहार है। इसलिए इसका संरक्षण करना मानव का पहला कर्तव्य है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर इस पर चिंतन करना जरूरी हो जाता है। यह दिवस उन वीरों को समर्पित होता है, जिन्होंने भारतीय जंगलों और उसमें रहने वाले तमाम बेजुबान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए खुद को मिटा दिया। यह दिन देश में हर साल की तरह 11 सितंबर को मनाया गया। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विशेष रूप से इस तिथि को चुना था। इसे 1730 में हुए ऐतिहासिक ह्यखेजरली नरसंहारह्ण के साथ भी जोड़ा जाता है, ताकि लोग उस घटना को याद कर सकें। खेजरली नरसंहार भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है, जिसे कोई भूल नहीं सकता। घटना बिश्नोई समुदाय से जुड़ी है, जिनके सदस्यों ने मारवाड़ साम्राज्य में पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। उनके 363 सदस्यों ने महाराजा अभय सिंह राठौर के आदेश पर खेजरी के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। पेड़ों के प्रति उनका ऐसा बलिदान, जिसे सुनकर लोगों की आज भी रूह कांप उठती है। वनों की मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो करीब एक तिहाई जंगली हिस्सा इंसानों ने अपनी जरूरतों के लिए रौंद दिया है। भारत में वनों और वृक्षों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2.91 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्ष की बहुतायत है। आज का खास दिन जनमानस को वन संपदा और जंगली जानवरों की रक्षा के लिए जागरूक करने को समर्पित है, क्योंकि जिस हिसाब से वनों की कटाई और जानवरों की तस्करी हो रही है, उससे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां कहीं इन कुदरती उपहारों से वंचित न हो जाएं। तभी ये दिवस हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व की तरह मार्मिक याद दिलाता है। साथ ही उन वन रक्षकों, रेंजरों और अधिकारियों-कर्मचारियों को श्रद्धांजलि भी देता है, जो भारतीय वनों के संरक्षण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर चुके हैं और कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें, तो जंगलों से करीब 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक अर्जित होता है, जिसमें बीते 3 वर्षों में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज हुई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन बताई गई है। ये तब है, जब कई राज्यों में वन सिमट गए हैं। दुख इस बात का है कि वनीय क्षेत्र में मानवीय हिमाकतें धड़ल्ले से जारी हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश ही वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,ओडिशा और महाराष्ट्र आते हैं। फिर शीर्ष पांच राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश,मेघालय,मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। ये राज्य आज भी वन संपदा से लबरेज हैं। देश के यूटी राज्य तो वनहीन हैं। दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे प्रदेशों में जंगलों का नामोनिशान तक नहीं हैं। भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में जिन तकनीकों से वनावरण किया जा रहा है, ये तकनीक अभी तक सफल रही है। देश में वन और वृक्ष संसाधनों पर बनी पुरानी नीतियों, योजनाओं को दीर्घकालिक प्रबंधन में तब्दील करके नई धार देने की आवश्यकता है। वनों की रक्षा डिजिटल और आधुनिक किए जाने की दरकार है। मानव जीवन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, इसकी आज ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की दरकार है। केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनमें लोगों को बताना गया कि उनके अभियान से आमजन कैसे जुड़े और कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, क्योंकि बिना जागरूकता लाए, सफलता नहीं मिल सकती। गांव-देहातों की पाठशाला, स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक केंद्रों में वनों के महत्व, वन्यजीव संरक्षण और वन शहीदों द्वारा किए गए बलिदान के विषय में युवा पीढ़ी को नियमित रूप से शैक्षिक कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशालाओं के जरिए जागरूक करते रहना चाहिए।

शिमला में रोष

शिमला देश के सुंदर, शांत और शालीन शहरों में शुमार है, पर आजकल वहां की हवा में जो तनाव व्याप्त है, वह न केवल दुखद, बल्कि शर्मनाक भी है। शिमला में बुधवार को तनाव फैल गया, जब एक कथित अवैध मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों लोग पुलिस से ही भिड़ गए। महिलाओं को भी बड़ी संख्या में धर्मस्थल विशेष के खिलाफ नारे लगाते देखा गया, यह सही संकेत नहीं है। प्रदर्शन चिंता की बात नहीं है, लेकिन पुलिस से भिड़ जाना गंभीर बात है। क्या ऐसे प्रदर्शन से बचा जा सकता था। क्या पुलिस या प्रशासन पहले से सजग नहीं था। क्या प्रदर्शन की तीव्रता का अंदाजा नहीं लगाया गया था। शिमला में जो हुआ है, उसने पुलिस को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो आश्चर्य नहीं। कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे प्रदर्शन की नौबत ही न आने पाए। पुलिस को पानी की बौछार और हल्के बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा है, पर ऐसी जरूरत आगे नहीं पड़नी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी मस्जिद में अवैध निर्माण हो रहा था, तो क्या इसे रोकने की जिम्मेदारी भीड़ की तो नहीं हो है। आखिर किसी धार्मिक समूह को ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई। बहुसंख्यक वर्ग के समूहों ने जब विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, तभी प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए था। भीड़ को न केवल जुटने दिया गया, बल्कि उसे आगे बढ़कर प्रदर्शन भी करने दिया गया। प्रशासन की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने के हरसंभव उपाय करे। प्रशासन कतई यह एहसास न होने दे कि उसकी सहानुभूति किसी वर्ग विशेष के साथ है। अगर प्रशासन पक्षपात करता न दिखे, तो ऐसे प्रदर्शन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। कहीं न कहीं प्रशासन की उदासीनता ने प्रदर्शनकारियों को मौका दिया है। अगर अवैध निर्माण है, तो उसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन को स्वयं ही कार्रवाई करनी चाहिए और अगर निर्माण अवैध नहीं है, तो विरोधी पक्ष को आश्वस्त करना भी प्रशासन का ही काम है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

What a JVP President may mean for India

AFTER a tumultuous three years during which Sri Lanka went broke and public protests forced the President to flee the country, it will elect a new President on September 21.The next President has to steer the country through the economic crisis, engage with the IMF over the financial bailout it received in 2023, address pending post-war issues of justice and accountability as well as political resolution of the Tamil question. He (all candidates are male) must also deal with the regional rivalry between India and China and big power geopolitics in the Indian Ocean.

A record 38 candidates are in the fray. Only three count. Incumbent Ranil Wickremesinghe, who took charge after President Gotabaya Rajapaksa fled, is banking on his two-year record of managing a bankrupt country and his acceptability to the international donor community. Sajith Premadasa, son of late President Ranasinghe Premadasa who was assassinated by an LTTE suicide bomber in 1992, is campaigning on his promise of a just government that works for "the welfare of all". Anura Kumara Dissanayake of the National People's Power, a coalition led by the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), who contested the elections in 2019, and polled just over three per cent of the vote, is campaigning as the candidate of the 'change' that voters want to see.Of the three, the 75-year-old Wickremesinghe is the only one who can claim experience of running a government. But he appears least likely to win. He is literally alone in this race, with no party or political support to speak of. His United National Party (UNP) is close to extinction after its rout to nil seats in the 2020 parliamentary election. Wickremesinghe's presidency is propped up in Parliament by the Sri Lanka Podujana Peramuna, the party of the reviled Rajapaksas. This association has made him even more unpopular. Plus he is taking the rap for conditions imposed by the IMF in return for its bailout package, negotiated on his watch, which have inflicted more economic pain.Premadasa is far more popular than Wickremesinghe. He walked out of the UNP with several others in 2020 when he realised Wickremsinghe would never hand over the party leadership to him. His Samagi Jana Balawegaya (SJB) or United People Power won more than 50 seats in Parliament, and is stronger than the parent party.He won brownie points for not succumbing to the lure of the prime ministership or the presidency in 2022 when it became evident he would have to depend on the Rajapaksas to keep him in office. Premadasa has promised to renegotiate the IMF deal so that its conditions do not hurt the people. He is going all out to woo not just the majority Sinhalese voters, but also the Tamil and Muslim communities. He is the only candidate to mention in his manifesto the 13th Amendment, a provision in the Sri Lanka Constitution to share political power with Tamils, with the promise of its "full implementation". This may hurt his campaign in the Sinhalese south, where devolution and federalism are bad words, much like Article 370 in India.Dissanayake is said to be the strongest contender. He is seen by most young voters as the symbol of "system change", the demand of the public uprising against the Rajapaksas. He was the first to call for renegotiating the IMF deal. The party's formidable cadre-based grassroots mobilisation has been laying the groundwork for over three years. But for those old enough to have witnessed the JVP's insurgencies in 1971 and from 1987-1990, the promise of Dissanayake is laced with memories of the violence of those years, and concerns about its political ideology.The JVP, which began as a radical left organisation, was banned after its first attempt to take over the state. But the JVP rose up again in 1987 against the Sri Lanka state, this time as a Sinhala chauvinist force opposing the Indian intervention that led to political concessions to the Tamil minority in the 13th Amendment to the Constitution, and the arrival of the Indian Peace Keeping Force in northern Sri Lanka.

SEBI's credibility at stake

Allegations against chairperson Madhabi Puri Buch highlight deep systemic failures

THE integrity of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which regulates the fifth largest capital market in the world, is under intense scrutiny. Revelations involving SEBI chairperson Madhabi Puri Buch are spilling out on a daily basis, raising significant concerns about conflict of interest and inadequate disclosures at the top of this critical institution. In fact, held to the standards of its own orders regarding disclosures by key management persons (KMP) of listed companies and insider trading, it is clear that the chairperson's transparency is woefully inadequate.So far, three sets of entities are making these allegations: Hindenburg Research was the first to put out 'whistleblower' documents, alleging conflict of interest; the Congress party has held a series of press conferences, making a series of charges and demanding an independent inquiry; and Subhash Chandra Goel, founder of the Zee group and himself under SEBI's lens, has levied charges of corruption against Buch.

A few things stand out and beg clear answers. They are based on the very standards that SEBI has applied to market participants, financial intermediaries, market infrastructure institutions and listed companies while filing prosecution cases against them or levying serious penalties on them.The first thing is by Hindenburg Research — about Buch's failure to recuse herself from the Adani investigation although she and her husband had offshore derivative investments in the same set of nested entities that were under a high-profile investigation of the Adani group, monitored by the Supreme Court. Hindenburg's second allegation is that she continues to hold a 99% stake in a private advisory entity — which is admittedly being used by her husband since his retirement — and has received income from 'well-known' Indian entities.The Congress first said that during her current employment as a regulator, she earned five times as much as (Rs16.80 crore) she did in ICICI Bank. It turns out that Buch was exercising shares granted to her under the Employee Stock Options Plan (ESOPs). Given that SEBI has handled several regulatory issues pertaining to ICICI Bank, the fact that Buch exercised ESOPs almost every year and benefited from the price rise raises disclosure issues and questions about whether she had access to unpublished price-sensitive information when she exercised her ESOPs. The Congress has also released documents about the renting of her personal property to the associate of a listed entity which has been under SEBI's investigation.A separate issue has simultaneously blown up. It pertains to SEBI employees' discontent over the unprofessional work culture, unreasonable productive expectations and issues relating to perks, housing allowances and compensation. Like the Hindenburg allegations, this was badly handled, leading to a public protest by a few hundred employees, asking the management to withdraw the inaccurate press release which claimed that employees were influenced by 'misguided external elements.' The SEBI employees claimed that the management was 'spreading lies about employees.'

This backdrop sets the stage for a deep dive into how these charges — the lack of adequate disclosures, appropriate recusal and the failure to sufficiently severe her financial ties upon transition to SEBI's leadership — impact SEBI's credibility in regulating the capital market and expose the absence of a robust framework to deal with conflict.In contrast, developed countries which have a revolving door between public and private sectors provide a sharp counterpoint. In the US, regulatory chiefs are required to divest themselves of holdings that could present potential conflicts or place such assets in a blind trust. Such stringent measures ensure that the individuals in public positions as heads of regulatory bodies are free from influences that could compromise their roles. This principle is underscored by the famous Pinochet case, which held that judges should not only avoid actual impropriety but also the appearance of it.

SEBI demands high standards of transparency from those it regulates. The same strictures don't seem to apply to its own leadership, a hypocrisy not lost on market observers. Even more surprising is the National Democratic Alliance (NDA) government's decision to pretend that it has seen and heard nothing. The government, including the Finance Minister, has buried its heads in the sand. In the process, the powerful SEBI board has been rendered meaningless. Apart from the chairperson and three whole-time members, the board includes the Secretary, Department of Economic Affairs, the Secretary, Ministry of Economic Affairs, a Deputy Governor of the Reserve Bank of India and an academic, who is the public representative. There was a time, under the United Progressive Alliance (UPA) government, when a joint secretary in charge of capital markets was a SEBI board member and wielded more power than the chairperson. This time around, the SEBI board is behaving like the proverbial three monkeys who 'see no evil, hear no evil and speak no evil'.To my mind, their role as members of a regulatory body do not give them that choice. Contrast this with what SEBI expects from boards of listed companies. Over the past two decades, SEBI has repeatedly tightened corporate governance requirements and listed rules casting onerous responsibilities on independent directors in connection with corporate disclosures, price-sensitive information and fiduciary responsibility. Every time these directors fail to question the management, proxy advisory firms are quick to issue sanctimonious missives, highlighting their failure and advising institutional investors on how to respond.The government members on the SEBI board have an even greater responsibility to ensure that they meet a higher standard of transparency and accountability. By refusing to question the SEBI chairperson or conduct an impartial inquiry and take steps to protect SEBI's credibility, the SEBI board has clearly failed. This exposes an important loophole in the regulatory system. It shows that there is nothing that stakeholders can do to hold a regulator accountable if the administrative ministry and the government refuse to initiate corrective action. Most people seem to think litigation would also be futile.

GST Council meet

Central, state govts have fared poorly

IN its outcomes, the 54th meeting of the Goods and Services Tax (GST) Council has been a mixed bag. The wait for relief on 18 per cent GST on health insurance and life cover premiums has got longer. The council has chosen the standard response to the growing clamour to reduce the levy. A Group of Ministers has been asked to review the demand. That said, the stiff 50-day deadline for a relook at the tax structure indicates a sense of urgency. There is little to justify the high GST on insurance policies. A political consensus on rationalisation of the tax slabs will help in the quick resolution of the matter, hopefully in the November meeting of the council. A rate cut could significantly lower insurance costs for policyholders.A welcome course correction is the exemption of GST on research and development grants from the private and public sectors to recognised educational institutions. Several institutions across India had received show-cause notices last month, demanding unpaid taxes. Allegations of tax terrorism had put a question mark on the Centre's R&D policy push. The relief is expected to boost research programmes and achieve global tax parity. The decision to lower the GST on some cancer drugs from 12 to 5 per cent is in line with the Budget announcement on lower customs duty.

GST collections have risen steadily after the Covid-led dip. There's a perception, and not without reason, that both the Centre and the states are averse to changing the taxation structure when revenues are healthy. The multiplicity of slabs runs contrary to the aim of streamlining the complex taxation system. An organic tax readjustment based on positive or negative end results is essential.

Drone attacks in Manipur must set alarm bells ringing

The Indian establishment has been ambivalent in its approach to the resolution of the crisis in Manipur.

THE September 1 drone bomb attack on Koutruk and Kadangband villages in Manipur's Imphal West district marked an escalation in the violence between the Kukis and Meiteis. Two persons were killed and nine injured in this first such use of drones by insurgents to target civilians. This was followed by more attacks the next day. They destroyed three India Reserve Battalion bunkers at Meikhang village in Imphal East district.

Since the security forces have explicit 'shoot-at-sight' orders against those crossing the buffer zone between the valley and the hill tribes, this new mode of attack could become the preferred tactic by insurgents. These weaponised drones can operate between 500 m and 15 km. Capable of carrying various explosives, including hand grenades and mortar bombs, these can hover and capture images, adding to the threat complexity. Their value lies not just in their destructive ability, but also in documenting the kills.

The recent attacks targeted Meitei-dominated villages. The Kuki-Zo militias are suspected to be behind these attacks. The use of drones to target civilians has been documented since August 2021, when such attacks were witnessed in the neighbouring Myanmar, in areas bordering Mizoram, not far from south Manipur. The drones were being used by the People's Defence Force (PDF) against forces of the Myanmarese junta. The PDF is the armed wing of the Myanmarese National Unity Government, which has been Myanmar's government-in-exile since the military junta-led coup in February 2021. It now controls all areas across the Manipur border, except the two pockets of Moreh and Ukhrul. Some hardware and ammunition/bombs could have been sold by the PDF and other Myanmar rebel groups (some supported by China) to valley-based banned Meitei groups and groups of Chin-Kuki ethnicity that fuel the conflict in Manipur.

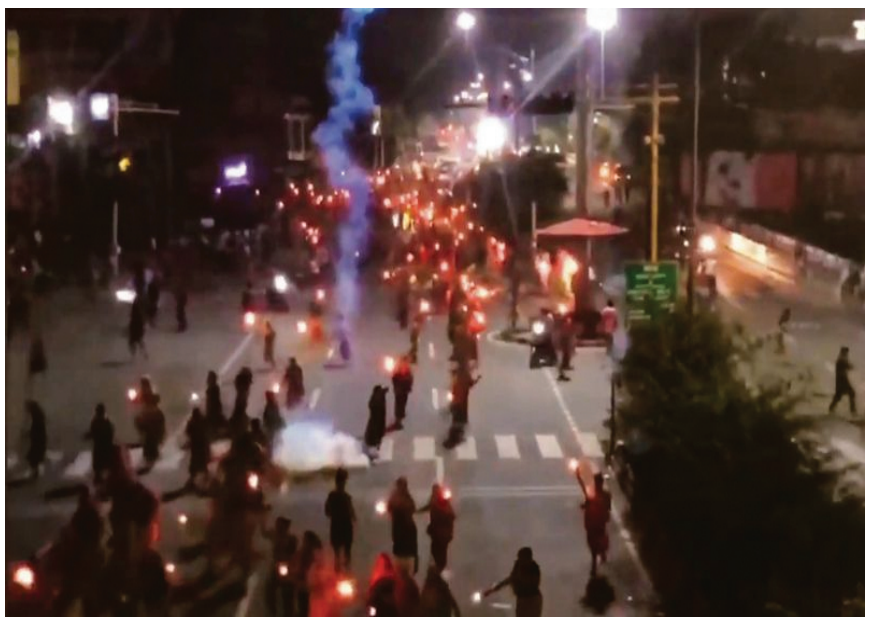

The security forces in the beleaguered Manipur are too busy separating the warring factions to guard the Indo-Myanmar border. Armed cadres belonging to the radicalised militia Arambai Tenggol and separatist terror group United National Liberation Front (UNLF) openly roam the streets and flaunt weapons (including those looted from state police armouries in May, last year). This, despite a peace agreement signed between the UNLF and the Centre in the presence of Home Minister Amit Shah in November, last year. Taking advantage of the ambiguity in the peace accord, UNLF cadres have not been restricted to camps and designated areas. Nor have weapons been withdrawn by the state government, which uses these Meitei militias to dominate the Imphal valley with impunity and challenge the remit of the Army and Assam Rifles (AR) checkpoints.The Army, AR and Central Armed Police Forces, which made tremendous sacrifices in the past while waging a successful battle against separatist elements, have effectively been sidelined by the removal of the Armed Forces (Special Powers) Act from the Meitei-dominated Manipur valley. The Army and the AR face a serious challenge in maintaining the fragile internal security situation, controlled by the predominantly Meitei state government. This freedom accorded by the state government to the factions responsible for last year's ethnic violence in Manipur is a serious security concern; the possibility of orchestrated violence or an offensive against the Kuki-Zo tribals and an escalation in armed response remains.

Two extraordinary threats to India's security have manifested themselves in the past four years. One threat is that of the Chinese incursions in Ladakh, which saw the occupation of Depsang, Chumar and Chang Chenmo by China's People's Liberation Army. Despite several rounds of negotiations and mutual disengagement in the Pangong Tso lake area, the status quo ante has not been restored, as demanded by the Indian Government. While the security forces are being augmented by weapon and equipment procurements (an inordinately long process), a gradual sidelining and deliberate diversion from the issue of incursions by the government and the media have fostered a sense of acceptance in the minds of the populace. This is an encouragement to China in many ways.

The second threat is the situation in Manipur that had been festering since early 2023 and escalated in May 2023. The ineptitude of the state government and the subsequent induction of 60,000 paramilitary forces and the Army by the Centre has not resulted in the de-escalation of violence. Conversely, new dimensions have emerged in the attacks, as the recent drone bombings show.The ongoing disturbances in Manipur have a debilitating effect on security as the open, porous border with Myanmar is ripe for exploitation. The Indian establishment has been ambivalent in its approach to the resolution of the crisis in Manipur. In the initial period, after clashes broke out in May 2023, the Centre had rushed Central and Army forces into the state. But thanks to a lack of coordination and partisan handling of the state police forces, which are predominantly Meitei, there was no let-up in the ethnic clashes. Then, in last December, the government took its eye off the ball and entered the General Election mode. Consequently, national security was relegated to local political expediency.

The escalation through drone bombings is an act of terror. The new level of the destabilising effects of a prolonged conflict and the exploitation of the situation by China should be of concern to the security establishment. Let us hope that it doesn't come to a point when concerted military action will be the only solution to the crisis.

Sensex, Nifty open in green as Fed rate cut hopes grow after US inflation data

The S&P BSE Sensex added230.45 points to 81,753.61, while the NSE Nifty50 gained 97.40 points to 25,015.85

New Delhi. Benchmark stock market indices opened higher on Thursday driven by gains in metals and IT stocks.This upward tick came as expectations for increased foreign inflows grew, following US inflation data that strongly indicated a Federal Reserve rate cut in the upcoming week.The S&P BSE Sensex added230.45 points to 81,753.61, while the NSE Nifty50 gained 97.40 points to 25,015.85 as of 10:28 AM.Dr VK Vijayakumar, Geojit Financial Services said that the latest US inflation numbers are mildly positive for markets."August CPI inflation coming at 0.2% has brought down the 12-month inflation to 2.5% from 2.9% earlier. This paves the way for a rate cut by the Fed in September. But since core inflation continues to remain high at 3.2% the Fed is likely to be cautious and refrain from a 50bp rate cut, finally settling for a 25bp rate cut. CPI inflation in India also is expected to be low at around 3.5% in August. This can facilitate a rate cut by the MPC in 2024 itself. In brief, the benign inflation conditions and prospects for rate cuts are positives for stock markets," he said.

"FIIs turning buyers in the cash market during the last three days is another indication that the market will continue to be resilient. The record Rs 3.23 lakh crore application money from 89 lakh investors for Bajaj Housing Finance IPO is a reflection of the humongous liquidity chasing stocks in the Indian market now. The bullish undercurrent of the market will continue," added Vijayakumar.

The Nifty Midcap100 index rose by 0.57%, while the Nifty Smallcap100 index also performed well, though more modestly, increasing by 0.36%, suggesting continued interest in smaller firms.

Meanwhile, the India VIX, often referred to as the fear gauge of the market, experienced a decline of 3.35%.

Early trade saw positive performance across all Nifty sectoral indices, with no sectors in the red.The healthcare sector led the gains, with Nifty Midsmall Healthcare rising 1.37% and Nifty Healthcare Index climbing 1.18%. Nifty Pharma also showed strong performance, increasing by 0.87%.The consumer-oriented sectors performed well, with Nifty Consumer Durables and Nifty FMCG advancing 0.87% and 0.42% respectively. The auto sector saw significant gains, with Nifty Auto rising 0.61%.Financial services sectors showed modest growth, with Nifty Financial Services up 0.27%, Nifty Financial Services 25/50 increasing 0.25%, and Nifty Bank climbing 0.25%. Nifty Private Bank saw a slight uptick of 0.17%, while Nifty PSU Bank performed better with a 0.61% increase.

Bajaj Housing Finance IPO allotment: Step-by-step guide to check status

New Delhi. The excitement surrounding IPOs has been strong this year, and Bajaj Housing Finance's IPO is no exception. Investors have eagerly put their money into the public issue, which appears to be on track to double their returns.Imagine a queue stretching miles with people vying for a golden ticket—that's how the Rs 6,560-crore IPO of Bajaj Housing Finance has felt as it attracted a mind-blowing Rs 3.2 lakh crore in bids.

The IPO received a total subscription of 67.43 times. As of 6:19 PM on September 11, 2024, the retail segment was subscribed 7.41 times, the qualified institutional buyer (QIB) category saw a subscription of 222.05 times, and non-institutional investors (NII) subscribed 43.98 times.Investors who have bid for Bajaj Housing Finance IPO can check their allotment status online. They can log in to either the BSE website or the website of Kfin Technologies Limited, the registrar for the issue.The latest Grey Market Premium (GMP) for Bajaj Housing Finance's IPO stands at Rs 74, as of 08:27 AM on September 12, 2024.Given the price band of Rs 70, the projected listing price for the IPO is Rs 144 (which is the cap price plus the current GMP). This suggests an anticipated gain of 105.71% per share.

The price band for Bajaj Housing Finance's IPO was set at Rs 66-70 per share. Investors could apply for a minimum of 214 equity shares, with applications accepted in multiples thereafter.

SpiceJet: HC orders to ground three engines

NEW DELHI. The Delhi High Court on Wednesday upheld a ruling mandating budget airline SpiceJet to ground three of its aircraft engines due to overdue payments to French lessors. A Division Bench, consisting of justices Rajiv Shakdher and Amit Bansal, decided not to overturn the previous single-judge order issued on August 14 regarding non-payment of dues for engines leased from two French companies.The airline had contested this order, but the Division Bench's ruling reinforces the enforcement of the initial directive.While pronouncing the judgement, the bench noted that "…The record reveals SpiceJet is in default, and past and current outstanding dues remain unpaid. At the risk of repetition, it must be stressed that SpiceJet has violated an agreed interim arrangement for payment of dues, which included a term that, upon breach, it would ground the engines that Team France and Sunbird France could then repossess".This ruling delivers a significant blow to SpiceJet, which has been grappling with financial challenges, including legal bttles over aircraft leases.

"….the fact that the financial condition of SpiceJet is weak is evident from its conduct and the stand taken on its behalf in court, which is that it is attempting to infuse funds through loans and/or equity. If the position in which SpiceJet is at this juncture, Team France and Sunbird France could well end up both without its engines or the monies due under the engine lease agreements." The bench modified the impugned order to a 'limited extent'.

Restructuring: Samsung to cut 200 jobs in India

NEW DELHI. Technology giant Samsung is planning to lay off nearly 200 employees in India as part of its cost-cutting measures, as per company sources.

The move is part of Samsung's global restructuring plan, which aims to cut up to 30% of its global workforce across various divisions. As per reports, the job cuts will primarily impact sales, marketing, and administrative staff in regions such as the Americas, Europe, Asia, and Africa.It has halted new hiring and is not filling roles left vacant by voluntary exits. Reports indicate its management recently summoned Indian team to South Korea to discuss ongoing issues and restructuring efforts.

In India, Samsung fell to third place in volume in the April-June quarter of 2024, as per IDC. Its smartphone shipments fell by 15.4%, marking its third consecutive quarterly decline, with its market share dropping to 12.9%. It is facing competition from rivals like Apple in the smartphone market and SK Hynix in the high-end memory chip sector.

In China, the company plans to cut 30% of its sales staff. It employed 267,800 people as of the end of 2023, with over half, or 147,000 employees, based overseas, according to its latest sustainability report.

UP to clear investment of Rs 10L cr soon'

NEW DELHI. The Uttar Pradesh government will soon organise the groundbreaking ceremony of investment proposals worth Rs 10 lakh crore, Chief Minister Yogi Adityanath said on Wednesday.

Inviting semiconductor industry to invest in the state, he highlighted that Uttar Pradesh offers incentives such as land subsidies and capital subsidies of 25% for chip units under a policy. Together with the Centre's incentives of 50%, chip units can get subsidies of up to

75% for investment proposals, the chief minister stated.Addressing the international conference on semiconductors, Semicon India, Adityanath said the state has attracted huge investment proposals from the industry.He recalled that a team which was preparing for an investor summit in the state earlier told him investment proposals of Rs 20,000 crore would come in UP. "Same Uttar Pradesh after 7 years has brought investment proposals of Rs 40 lakh crore.

Out of which, Rs 10 lakh crore was done in February. Rs 10 lakh crore investments are in pipeline, for which we will soon do a groundbreaking in the state," he said.

Ayushman Bharat to cover senior citizens above 70: All you need to know

New Delhi, The Union Cabinet has approved a major expansion of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) to cover all senior citizens aged 70 years and above.This change allows anyone in this age group to be eligible for health insurance, regardless of their income level.After the Cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw said, "Prime Minister Narendra Modi had made a commitment that all senior citizens above the age of 70 years will be given coverage under Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana. There are many families which are already covered and have senior citizens. In such families, additional coverage, top-up coverage will be Rs 5 lakh."This expansion aims to address the healthcare needs of the elderly, who often face higher medical expenses as they age.By lifting income restrictions, the government is ensuring that more senior citizens can benefit from much-needed health coverage, which will help ease the financial burden of healthcare.

How does the scheme work?

The AB PM-JAY now covers an additional 6 crore individuals from 4.5 crore families, focusing on seniors aged 70 and above. Each senior citizen will be given a health card, allowing them easy access to healthcare services under the scheme.The scheme provides Rs 5 lakh coverage annually per family. If there are multiple senior citizens in the same family, this coverage is shared among them. The scheme is particularly beneficial for nuclear families, where the financial burden on elderly members can be more difficult to manage.Eligibility - All senior citizens aged 70 and above are eligible for Rs 5 lakh health coverage, regardless of income or social status.

Top-up coverage - For families already enrolled in Ayushman Bharat, senior members will receive an extra Rs 5 lakh top-up, which is solely for their use.

Private insurance - Senior citizens with private health insurance can still take advantage of the scheme without any conflict with their existing coverage.

Public health schemes - Seniors who are part of other public health schemes like the Central Government Health Scheme (CGHS), Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS), or Ayushman Central Armed Police Force (CAPF) will need to choose between their current insurance and the new Ayushman Bharat health coverage.New health cards - All eligible senior citizens will receive a separate health card, which will help them access the scheme's benefits more efficiently.

Who pays for the coverage?

The cost of this expanded coverage will be Rs 3,437 crore initially. State governments will bear 40% of the expenses, while the Centre will cover the remaining 60%. For states in hilly and northeastern regions, the Centre will fund 90% of the costs.

Evs get Rs 11k crore boost from government

NEW DELHI: The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the proposal of the Ministry of Heavy Industries (MHI) for the implementation of 'PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme' to promote electric mobility in the country.

The PM E-DRIVE has replaced the FAME scheme and the temporary Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024. The new scheme has an outlay of Rs 10,900 crore over a period of two years. Subsidies/demand incentives worth Rs 3,679 crore have been provided to incentivise electric two-wheelers, electric three-wheelers, e-ambulances, e-trucks and other emerging EVs. The scheme will support 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-buses. There isn't much for electric car buyers.

The scheme allocates Rs 500 crore for the deployment of e-ambulances. A sum of Rs 4,391 crore has been provided for procurement of 14,028 e-buses by STUs/public transport agencies. The demand aggregation will be done by CESL in the nine

cities with more than 40 lakh population namely Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Ahmedabad, Surat, Bangalore, Pune and Hyderabad. Intercity and Interstate e-buses will also be supported in consultation with states. The scheme will promote the deployment of e-trucks in the country. Rs.500 crore has been allocated for incentivising e-trucks.The government said the scheme addresses range anxiety of EV buyers by promoting the installation of electric vehicle public charging stations (EVPCS). "These EVPCS shall be installed in the selected cities with high EV penetration and on selected highways. The scheme proposes installation of 22,100 fast chargers for e-4 Ws, 1,800 fast chargers for e-buses and 48,400 fast chargers for e-2W/3Ws. The outlay for EV PCS will be Rs 2,000 crore," said a statement issued by the Cabinet.Further, the government has approved an outlay of Rs 780 crore to modernise the test agencie. The Ministry of Heavy Industries (MHI) is introducing e-vouchers for EV buyers to avail demand incentives under the scheme.At the time of purchase of EV, the scheme portal will generate an Aadhaar authenticated e-Voucher for the buyer. A link to download the e-voucher will be sent to the registered mobile number of the buyer.

Zomato shares jump 4% to hit all-time high. Will it gain further

New Delhi, Zomato shares climbed 4% in early trading on Thursday, reaching an all-time high of Rs 283.50.At around 11:14 am, shares of the food delivery giant were trading 3.79% higher at Rs 282 apiece on the Bombay Stock Exchange (BSE).The rise comes after global brokerage firm UBS reaffirmed its bullish stance on the stock, maintaining a 'buy' rating and setting a target price of Rs 320.UBS cited strong growth prospects as the key driver behind its optimism.In a recent note, UBS highlighted that industry volumes grew by 2.5% month-on-month in August 2024, with adjustments made for the number of days.

The firm also pointed to the ongoing competitive dynamics between Zomato and Swiggy, describing the situation as a "push-and-pull" battle that has extended into Q2FY25.

Will it gain further?

UBS estimates that Zomato's Gross Merchandise Value (GMV) could see a 7% quarter-on-quarter rise for Q2FY25.The stock has been on a six-day winning streak, gaining 15.6% during this period.The rally gained momentum after Zomato closed its acquisition of Paytm's events and movie ticketing business.Following the deal, analysts from major global brokerage firms like Jefferies and JP Morgan have also turned bullish on Zomato's prospects.Earlier this month, JP Morgan revised its target price for Zomato to Rs 240, up from Rs 208, while maintaining an overweight rating.The brokerage believes Zomato is at the forefront of a retail transformation through its focus on convenience and selection in the quick commerce segment.The firm noted Zomato's successful expansion across metro cities, particularly in NCR, and raised its FY25-27 forecasts by 15-41%. Furthermore, Zomato's integration of its dining services with the newly acquired ticketing business has bolstered its growth outlook.Jefferies, another major brokerage, set a base target of Rs 335 for Zomato, reflecting a potential 31% upside.Jefferies is optimistic about Zomato's recent moves in the food delivery space, predicting a 20% compound annual growth rate (CAGR) in delivery revenue between FY24 and FY27.As per the agreement with Paytm, Zomato acquired the entire stake held by OCL in Orbgen Technologies Private Limited (OTPL) and Wasteland Entertainment Private Limited (WEPL). Both entities have now become fully owned subsidiaries of Zomato.In its latest financial results, Zomato reported a sharp increase in consolidated net profit, posting Rs 253 crore for the quarter ending June 30, 2024, marking a significant year-on-year jump.

Crude oil prices decline below $70; petrol, diesel unlikely to get cheaper

Brent Crude Future prices dropped below $70 a barrel on Tuesday, triggered by OPEC+'s downward revision of its demand forecast.

NEW DELHI. Even as crude oil prices declined below $70 a barrel for the first time since December 2021, analysts believe that petrol and diesel prices in India are unlikely to come down anytime soon.They indicated that oil marketing companies (OMCs) would prefer to see a sustained trend of lower crude prices for a longer period before making any decisions on domestic fuel prices.

"Oil marketing companies would possibly like to see sustenance of the trend of lower crude prices for longer before they take a call on prices," said Prashant Vasisht, VP & co-head, corporate ratings, ICRA.Brent Crude Future prices dropped below $70 a barrel on Tuesday, triggered by OPEC+'s downward revision of its demand forecast. Though the prices rebounded early on Wednesday, they fell below the $70 mark. Brent crude futures was trading at $69.68 a barrel and US West Texas Intermediate (WTI) crude at $66.37 at 7.56 PM IST.

"Crude oil prices have been depressed owing to repeated instances of increasingly weak demand from China even as US production is high at over 13 million barrels a day. Additionally, OPEC+ has extended oil production cut by two months leading to fears that there is disagreement on further production cuts leading to a bearish scenario. It is unclear whether this is a short term phenomenon as OPEC+ may after all increase cuts which could lead to increase in prices," said Vasisht.Indian oil Marketing companies have made revision of the prices of petrol and diesel across the country in March 2024 by Rs 2 per litre.Now, the elections approaching in Haryana and Jammu & Kashmir, there is speculation that oil marketing companies might consider reducing fuel prices. Moreover, Indian oil marketing companies, including Indian Oil Corporation Ltd (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), and Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), have reported significant profits in recent quarters, with a combined consolidated net profit of Rs 7,371 crore in the first quarter of this fiscal.

SC to deliver verdict on Sep 13 on Arvind Kejriwal's bail plea in excise policy case

- Kejriwal has filed two separate petitions challenging the denial of bail and against his arrest by the CBI in the corruption case filed by the central agency.

NEW DELHI. The Supreme Court is scheduled to deliver on Friday its verdict on Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's petitions seeking bail and challenging his arrest by the CBI in the excise policy 'scam'.

As per the cause list of September 13 uploaded on the apex court website, a bench headed by Justice Surya Kant is slated to pronounce the verdict.The bench, also comprising Justice Ujjal Bhuyan, had on September 5 reserved its verdict on the pleas.

Kejriwal has filed two separate petitions challenging the denial of bail and against his arrest by the CBI in the corruption case filed by the central agency.The AAP chief was arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI) on June 26. He has challenged in the apex court the Delhi High Court's August 5 order which upheld his arrest in the corruption case. The high court had noted that the loop of evidence against Kejriwal got closed after collection of relevant evidence following his arrest by the

CBI and it cannot be said that it was without any justifiable reason or illegal.

The high court had also granted him liberty to approach a trial court with his plea seeking bail in the case.The matter relates to alleged corruption in the formulation and execution of the Delhi government's excise policy for 2021-22, which has now been scrapped.The Enforcement Directorate (ED) has also lodged a separate money laundering case linked to the alleged excise policy 'scam'.According to the CBI and the ED, irregularities were committed while modifying the excise policy and undue favours extended to licence holders.

On July 12, the apex court had granted interim bail to Kejriwal in the money laundering case.

The top court had referred to a larger bench, preferably of five judges, for in-depth consideration of three questions on the aspect of "need and necessity of arrest" under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).The ED had on March 21 arrested Kejriwal in connection with the money laundering case.During the arguments on September 5 on Kejriwal's plea in the corruption case, the chief minister had vehemently opposed in the apex court the CBI's contentions that he should have approached the trial court first for bail in the corruption case.

Questioning the maintainability of Kejriwal's pleas, Additional Solicitor General S V Raju, appearing for the CBI, had submitted that even in the money laundering case in which he had challenged his arrest by the ED, he was sent back by the apex court to the trial court.

MCD captures stray cattle in Delhi's Keshavpuram zone

NEW DELHI. In an effort to tackle the issue of stray cattle and illegal dairies across the city, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) has launched a special drive in the Keshavpuram zone, leading to the impounding of 18 stray cattle on Wednesday.

The operation, carried out by the Veterinary Services Department with the assistance of local police, is part of MCD's larger plan to reduce the problem of stray cattle within its jurisdiction. The MCD has been actively conducting raids and impounding stray cattle in different parts of the city to address the ongoing issue. The corporation's veterinary department is also focusing on taking action against illegal dairies that contribute to the stray cattle problem.

An MCD spokesperson emphasised that the civic body is committed to addressing the menace of stray cattle and illegal dairies in urban zones. "This is just one step in a series of measures. More stringent action will be taken in the coming days," the spokesperson added. According to MCD data, 9,984 head of cattle have been impounded this year between January and July.

FORDA threatens nationwide strike if action taken against West Bengal junior doctors

FORDA president Dr Aviral Mathur said if the Bengal government initiates punitive action against the protesting junior doctors, "we will resume the nationwide strike."

NEW DELHI. Expressing solidarity with the junior doctors in West Bengal, who have defied a Supreme Court directive to return to work amid the state government's claims of a healthcare crisis, resident doctors in the national capital are contemplating a renewed strike.

The Federation of Resident Doctors Association (FORDA) has warned of escalated protests if any coercive action is taken to end their Bengal counterparts' peaceful demonstration.

"The movement for justice for Abhaya continues to be undermined by the very institutions meant to protect the rights and safety of our society," FORDA said in a letter."We had hoped for a swift and fair resolution to this horrific crime, but instead, the proceedings have taken a disappointing turn. It is not only the court's inaction but also the appalling defense put up by representatives of the West Bengal government, led by Kapil Sibal, that shocked us," the letter further read."We understand the anger, frustration and the deep sense of betrayal that has driven this protest. We will not allow it to be silenced," the letter said, adding that FORDA shall consider intensifying its protest after discussion with all stakeholder RDAs.

FORDA president Dr Aviral Mathur said if the Bengal government initiates punitive action against the protesting junior doctors, "we will resume the nationwide strike."

'Address women quota in DUSU polls': Delhi High Court

A bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela urged Delhi University to resolve the petition within three weeks.

NEW DELHI. The Delhi High Court on Wednesday directed the Delhi University Vice-Chancellor to swiftly address a representation seeking the introduction of women's reservation in the upcoming Delhi University Students' Union (DUSU) poll.

A bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Tushar Rao Gedela urged the university to resolve the petition within three weeks. Filed by Shabana Hussain and represented by advocate Ashu Bidhuri, the plea calls for a 50 per cent reservation for women in the DUSU polls, emphasising the lack of female participation due to the influence of money and muscle power in the elections.

It also calls for the Centre, UGC, and the university to reserve 50 per cent of seats for female candidates in both DUSU and college student union elections. The plea stresses the need for reservation for women to foster gender equality. It notes that a notification for the DUSU polls has been issued, with nominations starting on September 17, 2024, and the election scheduled for September 27, 2024.

Hussain has raised concerns about challenges faced by women despite 75 years of Independence. She underscored that the Constitution guarantees equality and participation for women, and highlighted the importance of political representation for women in a male-dominated society to achieve genuine empowerment.

'Bio-decomposer will be sprayed free of cost to stop stubble burning': Delhi environment minister

Stubble burning, included in this year's 21 focus points, also plays an important role in increasing the problem of pollution in the winter season.

NEW DELHI. Aiming to curb pollution during the upcoming winter months, the Delhi government has decided to spray bio-decomposers free of cost to decompose stubble in farmlands.

The government said that by spraying bio-decomposer, farmers will not have to burn stubble, which will prevent air pollution and will also increase fertility of fields.

Delhi Development Minister Gopal Rai, following a high-level meeting with officials and experts, announced that so far 841 farmers have already signed up for the initiative aimed at curbing pollution and promoting sustainable farming practices in both Basmati and non-Basmati paddy fields within the capital.

Giving more details about the meeting, Rai said, "In order to solve the problem of pollution occurring in the winter season inside Delhi, the Kejriwal government is constantly moving towards making its Winter Action Plan by meeting with different departments."

The Delhi Development Minister continued, "All the departments have been assigned different responsibilities on 21 focus points regarding the Winter Action Plan, under which the Environment Department will prepare a joint action plan for it. Stubble burning, included in this year's 21 focus points, also plays an important role in increasing the problem of pollution in the winter season."

He said that this year the government will spray bio-decomposer free of cost in more than 5,000 acres of land to decompose the stubble. Right now the farmers are being asked to fill the form.

No ventilator in Delhi govt-run hospital, six-day-old infant dies

The infant was battling breathlessness and high fever and was put on oxygen support, but without access to a neonatal ventilator, her condition deteriorated.

NEW DELHI. A six-day-old baby lost her life in the absence of a neonatal ventilator at a Delhi government-run hospital, sources said on Wednesday. The incident took place at Babu Jagjivan Ram Memorial Hospital on Tuesday in Jahangirpuri.Born to 24-year-old Kavita, the infant was battling breathlessness and high fever. She was put on oxygen support, but without access to a neonatal ventilator, her condition deteriorated.

"Since no neonatal ventilator was available, we put the child on oxygen support and administered antibiotics. Her SPO2 level was maintained with the support of oxygen. But she died," a doctor said.Hospital's Medical Superintendent Digbijoy Dutta said all nearby government hospitals, including Baba Saheb Ambedkar and Lok Nayak Hospital, were contacted but none of them responded positively. He said the hospital had only one ventilator bed, which was occupied by another patient.

Delhi BJP Sikh cell protests Rahul Gandhi's remark in US, seeks apology

NEW DELHI. The Delhi BJP's Sikh cell - Sikh Prakosth - on Wednesday staged a protest against Congress leader Rahul Gandhi for his alleged controversial remarks in the United States concerning Sikhs in India.

The protesters, including women, attempted to march towards Gandhi's residence but were not allowed by the police. As the protesters tried to disobey the police orders, they were subsequently detained but later released after a warning.The protesters demanded an apology from Gandhi, the Leader of Opposition in the lower house of Parliament, for his recent remarks in the US while addressing a gathering of Indian Americans in a Washington DC suburb. "The fight is about whether a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India or a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions," Gandhi had said.

BJP's Sikh Cell convener Sardar Charanjeet Singh Lovely condemned this statement and remarked that Congress has historically been the party that caused the most harm to Sikhs."The Sikh community and the nation can never forget or forgive these atrocities be it Operation Blue Star, Rahul Gandhi must apologise to the Sikhs across the country and retract his statement," Lovely said.

The Delhi BJP accused Rahul of being the first leader of the opposition who makes controversial statements on India's internal matters in front of the foreign media.

Party's national spokesperson RP Singh stated that Gandhi should refrain from making such statements, especially about the Sikh community. Meanwhile, Delhi BJP president Virendra Sachdeva also slammed Gandhi for his comments on caste-based reservation. Gandhi during his address had said that his party will "think of ending reservation when India is a fair place".

Gurgram battles civic woes as municipal polls pending for two years

Elections to the Municipal Corporation of Gurgaon (MCG) were last held in 2017, with the term of the councillors and the mayor ending in 2022.

NEW DELHI. Every year, the onset of monsoon brings about a familiar site for the residents of Gurgram - heavily waterlogged streets that make daily commute nearly impossible.

Residents often take to social media to ridicule the city's misgovernance with many sarcastically praising authorities for turning their flats into "sea-facing" luxury apartments.

Flooding, however, is not the only issue plaguing the 'Millenium City'. Residents frequently complain of overflowing sewers, water scarcity, damaged roads and irregular garbage collection. Some of the city's Residents Welfare Associations (RWAs) even went so far as to boycott the recently-held Lok Sabha polls until conditions improved.

"The situation has gotten consistently worse in the last 2-3 years," said Raj Kumar Yadav, president of Sector 46 RWA. According to Yadav, garbage collection is one of the worst-hit services with private contractors selling off their tenders from one to another with no accountability to residents."Garbage collection is usually delayed by several days and despite fixed rates for garbage collection, based on plot size, contractors also grossly overcharge us. These contractors are no better than goons and threaten us if we complain to the

Municipal Corporation," he said.The situation in private societies under the management of the Municipal Corporation of Gurgaon (MCG) is no better. Mayfield Garden, a private colony spread over 327 acres was recently taken over by the MCG. Residents had been pooling their funds together and managing the locality on their own ever since the group of builders that developed the area stopped its maintenance in 2012.

"We have made several representations to MCG officials but nothing has been done to improve our situation. A single hour of rain can easily flood our entire locality," said RK Sharma, president of Mayfield Garden- B RWA.

Notably, elections to the MCG House were last held in 2017, with the term of the councillors and the mayor ending in 2022. Fresh elections were supposed to be held within six months but were delayed as the delimitation exercise could not be completed. Elections can be held only after the delimitation is carried out and approved by the state government, said officials. In the absence of elected officials, residents' pleas often go unheard in the MCG.

According to Kuldeep Singh Bohra, who served as a councillor from 2017 to 2022, elected representatives play a crucial role in bringing residents' concerns to the attention of civic officials.

News box

'We Want Good Relations With India': In First Televised Address, Bangladesh's Yunus Calls For Fair, Equitable Ties

Dhaka, Bangladesh Bangladesh's Chief Adviser Dr Muhammad Yunus on Wednesday said his country wants good relations with India and other neighbouring nations onthe basis of "fairness and equality".

In a televised address, marking the first month of the interim government's formation, Yunus said after he took oath as the head of the administration, many foreign leaders, including Indian Prime Minister Narendra Modi and his Pakistani counterpart Shehbaz Sharif, telephoned to congratulate him.We want good relations with India and other neighbouring nations, but that relations should be on the basis of fairness and equality," he said.Yunus said Bangladesh has already started high-level bilateral cooperation talks with India to deal with floods."I have also taken the initiative to revive SAARC to enhance regional cooperation in South Asia," he said.SAARC comprises Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.

Typhoon Yagi sweeps through Vietnam: More than 170 dead, flood waters threaten Hanoi

World. While, the state-run power utility, EVN, announced on Wednesday that it had cut off power to some flooded areas of the capital due to safety concerns.Mai Van Khiem, director of the National Centre for Hydro-Meteorological Forecasting, stated that the Red River was at its highest level in two decades, with more rain expected over the next two days.The government has estimated that the typhoon and subsequent landslides and floods have killed 179 people, with 145 others reported missing.The Blue Dragon Children's Foundation, a charity, evacuated its office on Tuesday after authorities warned of flood risks. Spokesperson Carlota Torres Lliro expressed concern for the dozens of children and families living in makeshift houses by the river, news agency Reuters stated.EVN also reported that it had halted water discharge from the Hoa Binh hydropower dam, the second largest in northern Vietnam, into the Da River, a tributary of the Red River, to reduce water flow.Additionally, Vietnamese authorities have raised concerns about Chinese hydropower plants releasing water into another tributary of the Red River, the Lo River (known as Panlongjiang in China), though Beijing has stated that the two countries are cooperating on flood prevention."My house's first floor is completely under water. Now we have no fresh water and electricity," Nguyen Duc Tam, a 40-year-old resident of Thai Nguyen, about 60 km (37 miles) from Hanoi, told Reuters.

Factories and warehouses in coastal industrial hubs east of Hanoi have been severely affected, with many forced to close, potentially disrupting global supply chains.

From Chinese to Italians and beyond, maligning culture via its foods is longtime American habit

NEW YORK. It's a practice that's about as American as apple pie - accusing immigrant and minority communities of engaging in bizarre or disgusting behaviors when it comes to what and how they eat and drink, a kind of shorthand for saying they don't belong. The latest iteration came at Tuesday's presidential debate, when former President Donald Trump spotlighted a false online tempest around the Haitian immigrant community of Springfield, Ohio. He repeated the groundless claim previously spread by his running mate, JD Vance, that the immigrants were stealing dogs and cats, the precious pets belonging to their American neighbors, and eating them. The furor got enough attention that officials had to step in to refute it, saying there was no credible evidence of any such thing.But while it might be enough to turn your stomach, such food-based accusations are not new. Far from it.Food-related scorn and insults were hurled at immigrant Chinese communities on the West Coast in the late 1800s as they started coming to the United States in larger numbers, and in later decades spread to other Asian and Pacific Islander communities like Thai or Vietnamese. As recently as last year, a Thai restaurant in California was hit with the stereotype, which caused such an outpouring of undeserved vitriol that the owner had to close and move to another location.Behind it is the idea that "you're engaging in something that is not just a matter of taste, but a violation of what it is to be human," says Paul Freedman, a professor of history at Yale University. By tarring Chinese immigrants as those who would eat things Americans would refuse to, it made them the "other."

In the US, foods can be flashpoints

Other communities, while not being accused of eating pets, have been criticized for the perceived strangeness of what they were cooking when they were new arrivals.

Biden, Trump, Kamala Harris appear together at 9/11 ceremony in New York

New York With presidential candidates looking on, some 9/11 victims' relatives appealed to them on Wednesday for accountability as the US marked an anniversary laced with election-season politics.In a remarkable tableau, President Joe Biden, former President Donald Trump and Vice President Kamala Harris stood together at ground zero just hours after Trump and Harris faced off in their first-ever debate. Trump and Biden — the successor whose inauguration Trump skipped — shook hands, and former New York Mayor Michael Bloomberg appeared to facilitate a handshake between Harris and Trump.Then the campaign rivals stood only a few feet (meters) apart, Biden and Bloomberg between them, as the hours-long reading of victims' names began. At Trump's side was his running mate, Senator JD Vance.The image was one of putting politics aside at this year's solemn commemoration of the hijacked-plane attacks that killed nearly 3,000 people on September 11, 2001. But some victims' relatives, after reading out names, delivered political messages of their own."We are pleading for your help, but you ignore us", Allison Walsh-DiMarzio said, directly challenging Trump and Harris to press Saudi Arabia about any official involvement in the attacks. Most of the 19 hijackers were Saudi, but the kingdom denies it was behind their plot."Which one of you will have the courage to be our hero? We deserve better", Walsh-DiMarzio said. She's a daughter of 9/11 victim Barbara P Walsh, an administrative assistant.Joanne Barbara was one of multiple readers who spoke out against a now-revoked plea deal that military prosecutors struck with alleged 9/11 mastermind Khalid Sheikh Mohammed and two fellow defendants."It has been 23 years, and the families deserve justice and accountability", said the widow of Assistant Fire Chief Gerard A Barbara.Biden, on his last September 11 in office, and Harris paid respects on Wednesday at all three 9/11 attack sites: ground zero, the Pentagon and a rural part of Pennsylvania.The president, vice president — and, separately, Trump — laid wreaths on Wednesday afternoon at the Flight 93 National Memorial near Shanksville, Pennsylvania. Biden and Harris spoke with

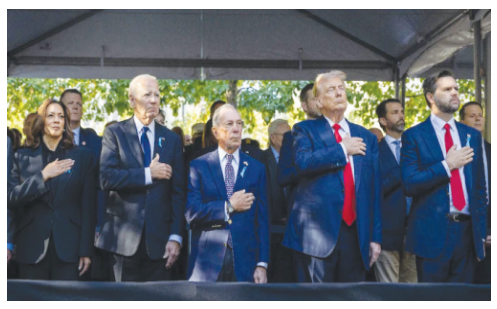

victims' relatives and visited the local fire department; Trump and Vance went to a New York City firehouse earlier in the day.The Flight 93 memorial stands where one of the hijacked planes crashed after crew members and passengers tried to storm the cockpit. Trump described the site as an "incredible place" in brief remarks from afar to reporters.The attacks killed 2,977 people and left thousands of bereaved relatives and scarred survivors. The planes took down the World Trade Center's twin towers and carved a gash in the Pentagon, the US military headquarters, where Biden and Harris laid a red, white and blue wreath on Wednesday afternoon.While many Americans may not observe 9/11 anniversaries anymore, "the men and women of the Department of Defense remember", Defense Secretary Lloyd Austin said earlier in the day.The attacks altered US foreign policy, domestic security practices and the mindset of many Americans who had not previously felt vulnerable to foreign extremists.Effects rippled around the world. Victims came from more than 90 different countries, and the US responded to the attacks with a "Global War on Terrorism". US-led invasions of Afghanistan and Iraq killed hundreds of thousands of Afghans and Iraqis and thousands of American troops.Communities around the country hold events on the anniversary, which Congress has titled both Patriot Day and a National Day of Service and Remembrance.

Thousands of Americans comemorate it with volunteer work — among them Harris' running mate, Minnesota Governor Tim Walz. He packed meals in St. Paul for people in need.

Ohio man slams Trump, Vance for politicising son's death in immigration row

World During Tuesday's presidential debate, Donald Trump referenced Springfield, Ohio, as an example to criticise immigration and attack Kamala Harris. He alleged, "Look at Springfield, Ohio, or Aurora, Colorado. Immigrants are taking over towns, violently occupying buildings. These are the people Biden and Harris have allowed in, and they are destroying our country. They're dangerous and at the highest level of criminality."Meanwhile, in Springfield, just an hour before the debate, Nathan Clark, father of an 11-year-old boy named Aiden who died in a crash involving an immigrant's vehicle, spoke out against Trump and his ally JD Vance. Speaking at a Springfield City Commission meeting, Clark condemned the politicians for exploiting his son's death to spread hate.The 11-year-old had died after a car crossed the centreline on a two-lane road and struck a school bus carrying dozens of children. Clark, who

was thrown off the bus as it veered off the roadway and flipped, died on the spot.Hermanio Joseph, a 35-year-old Haitian national, was behind the wheels of the car that caused the accident. He was convicted of involuntary manslaughter in May and faces up to nine years in prison.

The incident, which occurred over a year ago, became a flashpoint for growing tensions about the influx of Haitian immigrants to the area.

The debate intensified after JD Vance, a political ally of Trump, brought national attention to Springfield's demographic changes, labelling them as harmful consequences of Biden's border policies. These immigrants, who have legal status and work permits, have moved to Springfield to fill jobs in manufacturing and other industries. However, Vance's remarks have stoked fears and amplified false narratives.The Trump campaign further escalated the issue by posting on social media about Aiden, featuring his picture alongside that of Hermanio Joseph, the Haitian immigrant involved in the crash.Vance went a step ahead and alleged that "a child was murdered by a Haitian migrant."However, the politicisation of Aiden Clark's death is something that his parents never wanted and have now spoken against.During the meeting on Tuesday, Nathan Clark, standing beside his wife Danielle, expressed his heartbreak and frustration over the manipulation of his son's death.

Tajikistan's chief mufti injured in attack in Dushanbe mosque

World. Tajikistan's top Muslim cleric Sayeedmukarram Abduqodirzoda got injured in a stabbing attack outside a mosque in the capital city on Wednesday.

Abduqodirzoda, the chairman of the country's Islamic Council of Ulema, was attacked following a prayer service in Dushanbe, the interior ministry said as reported by Reuters.The attacker was detained, and authorities have launched an investigation into the incident.Abduqodirzoda, 61, a respected religious leader in the predominantly Sunni Muslim country, sustained minor injuries and was released from the hospital.

34 killed as Israeli airstrikes hit United Nations school, homes in Gaza

Gaza Strip Israeli airstrikes across Gaza overnight and Wednesday hit a UN school sheltering displaced Palestinian families as well as two homes, killing at least 34 people, including 19 women and children, hospital officials said. A UN official said six staffers were among the dead.The war in Gaza is now into its 11th month, with tens of thousands of people dead, and international efforts to mediate a cease-fire between Israel and the Hamas militant group have repeatedly stalled as they accuse each other of making additional and unacceptable demands.In the occupied West Bank, Israeli troops launched raids in several towns backed by airstrikes, continuing a crackdown across the territory that the military says is targeting militants but has wrecked neighbourhoods and killed civilians. One airstrike killed five people the military said were militants threatening its troops. A second strike on a car killed at least three people, the Palestinian Health Ministry said.An attacker crashed a fuel truck into a West Bank bus stop near the Israeli settlement of GIvat Assaf, killing an Israeli soldier, the military said. Officials said soldiers and an armed civilian "neutralised" the attacker.The strike on the UN's al-Jaouni Preparatory Boys School in the Nuseirat refugee camp killed at least 14, including two children and a woman, officials from Awda and al-Aqsa Martyrs hospitals said. At least 18 other people were wounded, they said.The Israeli military said it was targeting Hamas militants planning attacks from inside the school. The claim could not be independently confirmed.One of the children killed was the daughter of Momin Selmi, a member of Gaza's civil defence agency, which rescues wounded and retrieves bodies after strikes, the agency said.Gaza's schools are packed with tens of thousands of Palestinians driven from their homes by Israeli offensives and evacuation orders. The al-Jaouni school, one of many in Gaza run by the UN agency for Palestinians, or UNWRA, has been hit by multiple strikes during the war.UNRWA said six staffers aiding the displaced, including the manager of the shelter, were killed. "Humanitarian staff, premises & operations have been blatantly & unabatedly disregarded since the beginning of the war," the agency's director, Philippe Lazzarini, wrote on X.

Peru's ex-President Alberto Fujimori, convicted for human rights abuses, dies

Lima Former Peruvian president Alberto Fujimori, who steered economic growth during the 1990s but was later jailed for human rights abuses stemming from a bloody war against Maoist rebels, died on Wednesday. He was aged 86.Close colleagues visited him earlier in the day, reporting that he was in a critical condition."After a long battle with cancer, our father... has just departed to meet the Lord," his daughter Keiko Fujimori wrote in a message on X, also signed by te former leader's other children.Fujimori, the son of Japanese immigrants, was the little-known chancellor of a farming university when elected to office in 1990. He quickly established himself as a cunning politician whose hands-on style produced results even as he angered critics for concentrating on power.He slayed hyperinflation that had thrown millions of Peruvians out of work, privatised dozens of state-run companies, and slashed trade tariffs, setting the foundations for Peru to become, for a while, one of Latin America's most stable economies.Under his watch, the feared leader of the Maoist Shining Path, Abimael Guzman, was captured - dealing a crucial blow to a movement that in the 1980s seemed close to toppling the Peruvian state. Guzman died in prison in September 2021.

But many Peruvians saw Fujimori as an autocrat after he used military tanks to shut down Congress in 1992, redrafting the constitution to his liking to push free-market reforms and tough anti-terrorism laws.

A slew of corruption scandals during his 10-year administration also turned public opinion against him.Shortly after he won a third election in 2000, amending the constitution to run, videos emerged of his top adviser and spy chief Vladimiro Montesinos doling out cash to bribe politicians. Fujimori fled to exile in Japan.

He resigned via fax from Tokyo and then unsuccessfully campaigned for a Japanese senatorial seat.Montesinos was later captured in Venezuela and jailed, convicted for the hundreds of videos he recorded of himself handing out cash bribes to politicians and business and media executives.The cases against Fujimori piled

up, including accusations that he had ordered the use of death squads in his battle against Shining Path militants.Fujimori was safe in Japan - he was a dual citizen and Japan does not extradite its citizens. So many were shocked when, in 2005 he decided to head back to Peru, apparently in hopes of forgiveness and a return to politics.Instead, he was detained during a layover in Chile, extradited to Peru in 2007, and in 2009 he was convicted and sentenced to 25 years in prison.

'FUJI-SHOCK'

Once jailed, Fujimori's public appearances were limited to hospital visits where he often appeared dishevelled and unwell.While detractors dismissed his health complaints as a ploy to get out of prison, then-president Pedro Pablo Kuczynski briefly pardoned Fujimori in 2017.Months later, Kuczynski was impeached, and the pardon overturned by Peru's top constitutional court, sending Fujimori back to the special prison that held him and no other inmates.The court restored the pardon in December 2023, releasing the ailing Fujimori, who had suffered from stomach ulcers, hypertension and tongue cancer. In May 2024, Fujimori announced he had been diagnosed with a malignant tumour.Fujimori's legacy has been most passionately defended by his daughter Keiko, who has been close to clinching the presidency herself three times on a platform that has included pardoning her father and defending his constitution.The late Fujimori was born in Lima on Peruvian Independence Day, July 28, 1938.A mathematician and agricultural engineer, Fujimori was a political nobody when he decided to run for the presidency.

Who is Ilhan Omar, US Congresswoman whose meeting with Rahul Gandhi sparked row

World Congress leader Rahul Gandhi's meeting with Ilhan Omar, a US House of Representatives member, has stirred a row with the BJP condemning it over her alleged anti-India stance.The BJP leaders cited Omar's comments on the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar, her views on Kashmir, and her visit to Pakistan, among other actions, to criticise the Congress leader's meeting.

WHO IS ILHAN OMAR?

Ilhan Omar represents Minnesota's 5th Congressional District in the US House of Representatives, which includes Minneapolis and surrounding suburbs.A policy analyst, organiser, public speaker and advocate, Omar was sworn into office in January 2019, making her the first African refugee to become a Member of Congress and the first woman of colour to represent Minnesota. She was one of the first two

Muslim-American women elected to Congress.Born in Somalia, Omar and her family fled the country's civil war when she was eight. The family spent four years in a refugee camp in Kenya before coming to the United States in 1990s. In 1997, she moved to Minneapolis with her family.Before entering politics and running for office, she worked as a community educator at the University of Minnesota, was a Policy Fellow at the Humphrey School of Public Affairs and served as a Senior Policy Aide for the Minneapolis City Council.Omar is the Vice-Ranking Member of the House Budget Committee. She also serves on the House Education and Workforce Committee, where she is a member of the Subcommittee on Workforce Protections and Subcommittee on Health, Employment, Labour, Pensions (HELP).

She is the Deputy Chair of the Congressional Progressive Caucus and Vice-Chair of the Medicare For All Caucus.

ILHAN OMAR'S 'ANTI-INDIA' STAND

In September 2023, Omar said the US must fully support the Canadian investigation into India's alleged role in the assassination of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar.

She also introduced a resolution to condemn alleged human rights violations and violations of international religious freedom in India, including those targeting Muslims and other religious minorities.

In June 2023, Omar boycotted Prime Minister Narendra Modi's address to the US Congress.She introduced a resolution in June 2022 calling on the US Secretary of State to designate India as a country of particular concern for alleged violations of religious freedom.In April 2022, she visited Pakistan, met with top Pakistani leaders, including former Prime Minister Imran Khan, and travelled to Pakistan-Occupied Kashmir (POK). India condemned the US Congresswoman's visit to POK.In 2019, she also criticised the National Register of Citizens (NRC) in Assam, calling it a part of the "Hindu nationalism project" of PM Modi. She has also been openly critical of the decision to abrogate Article 370 in Jammu and Kashmir.

NEWS BOX

Vinicus apologises to fans for Brazil defeat, addresses Real Madrid comparisons

New Delhi. Brazilian winger Vinicius Junior issued an apology to fans following Brazil's 0-1 defeat to Paraguay in the FIFA World Cup Qualifiers on September 11. This loss continued Brazil's troubling run, leaving them in a precarious position in the CONMEBOL standings. In his statement, Vinicius expressed regret for the team's poor form and assured fans of his commitment to improving his own performance.Vinicius acknowledged the difficult situation Brazil is in, as the five-time World Cup winners now sit fifth in the standings with just 10 points from eight games. This places them behind Argentina, Colombia, Uruguay, and Ecuador, and only narrowly ahead of Venezuela on goal difference. With only

the top six teams qualifying for the World Cup, Brazil's current position is alarming.

"We apologise to the fans, who are always on our side...But this is a difficult time, we just want to improve... I know my potential, I know what I can do for the national team. Of course it's been a very difficult process, because when you don't have confidence, you don't get goals, you don't get assists and good performances," Vinicius told Sportv"We know the situation we're in, we want to get Brazil out of this situation at any cost, we all have to go home now and start thinking about what we can do to get back to playing well. We cannot come here, lose these points and play the way we did," Vinicius added.Vinicius also addressed criticism regarding his performances, noting that while he has excelled at Real Madrid, he has struggled to replicate that success with the national team. He promised to work harder to meet expectations.

"It's completely different [tharazil's next World Cup Qualifiers will be crucial, with matches against Chile on October 11 and Peru to follow. These games will be vital for Brazil's hopes of securing a spot in the tournament, and for Vinicius, who will be under pressure to lead his team to victory and turn their fortunes around.

Is Carlos Alcaraz's second-half slump in 2024 a cause for concern

New Delhi Carlos Alcaraz and Jannik Sinner have solidified their status as the leaders of the next generation in men's singles tennis, sharing all four Grand Slam titles between them in 2024. Alcaraz claimed victories at the French Open and Wimbledon, while Sinner completed the hard-court double,

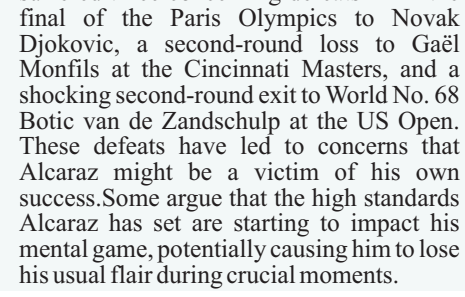

winning both the Australian Open and the US Open, heading towards finishing the year as the World No. 1.While Sinner's performance only grew stronger, culminating in his US Open triumph after successfully distancing himself from the noise surrounding his doping case, Alcaraz experienced a late-season slump. Though not alarming, questions have surfaced about the Spaniard's ability to win on his bad days — a trait that often distinguishes legends from the rest.In 2023, Roger Federer expressed concerns about placing immense pressure on young tennis stars, cautioning that unrealistic expectations could hinder their development. It seems the very scenario Federer warned about may now be unfolding."I always don't like to put too much pressure on younger players, especially like, 'He's going to do this.' But he's (Alcaraz) the type of player who says, 'Well, I'm coming to Wimbledon, I'm coming to win. I'm coming to Paris, I'm coming to win.' So he's putting that pressure on his own, which is great," Federer told CNN Sports in 2023.Despite Alcaraz's impressive achievements in 2024, some fans have been quick to speculate whether the mounting pressure is beginning to affect the four-time Grand Slam champion. Since his Wimbledon triumph in July, Alcaraz has suffered three concerning defeats — in the final of the Paris Olympics to Novak Djokovic, a second-round loss to Gaël Monfils at the Cincinnati Masters, and a shocking second-round exit to World No. 68 Botic van de Zandschulp at the US Open. These defeats have led to concerns that Alcaraz might be a victim of his own success.Some argue that the high standards Alcaraz has set are starting to impact his mental game, potentially causing him to lose his usual flair during crucial moments.

Ponting praises 'rough diamond' Jake Fraser McGurk: Can be an all-format player

Ricky Ponting has hailed young Jake Fraser-McGurk as a future all-format star for Australia but cautioned that the 22-year-old must refine his aggressive style to fulfill his potential as a key player for Australia.

Southampton. Former Australia captain Ricky Ponting has heaped praise on young batter Jake Fraser-McGurk, highlighting him as one of the most promising talents in world cricket. While Ponting lauded Fraser-McGurk's explosive batting abilities, he also pointed out that the 22-year-old has room for improvement, particularly in refining his style of play.

Although Fraser-McGurk did not feature in Australia's first T20I against England on September 11 at The Rose Bowl, his reputation as a hard-hitting batsman has grown significantly since his debut in the Indian Premier League (IPL) in 2024 with the Delhi Capitals. Ponting, speaking to SkySports, emphasized that Fraser-McGurk's potential is immense, and with a more well-thought-out approach, he could become a key player for Australia across all three formats."He's an extreme talent. He's a a ball striking talent. He's still very much of a rough diamond though. Like I, I'm not sure in his own head he's actually worked out exactly the right way to go about it yet. I mean, he only goes one way, but when he's thinking about hitting the ball to different parts of the ground is when you see the best Jake Fraser-McGurk quite often," Ponting said."He'll get sort of stuck in trying to hit him one which is normally down over long on or to mid wicket. But if he thinks about scoring 360 degrees around the ground, he's as clean a striker as I think I've ever seen. He's probably 5 ft 10, he's not a big kid, but he hits the ball extremely hard and he's got no fear, and he's a gun in the field. He's someone that I think that in the future can be a three-format player for Australia," Ponting added.Ponting's remarks come at a time when Australian cricket is transitioning after the retirement of veteran opener David Warner. Cricket fans and pundits alike have been quick to predict Fraser-McGurk as a potential successor at the top of the order, a role he has performed brilliantly for Delhi Capitals in the IPL.

Despite his absence from the T20I series opener against England, Fraser-McGurk remains a player to watch. Ponting's comments underline the belief in the young batter's ability to rise to the occasion, provided he continues to develop his game.

As Australia looks to the future, Fraser-McGurk's journey will be closely followed by fans eager to see if he can fulfill the high expectations set by legends like Ponting. The young batter's aggressive style and potential to become a mainstay in the national team make him one of the most exciting prospects in Australian cricket.

Unstoppable Jannik Sinner will make things difficult for Alcaraz: Toni Nadal

New Delhi. Toni Nadal, the uncle and former coach of tennis legend Rafael Nadal, recently showered praise on Jannik Sinner, the current World No. 1, following his impressive US Open triumph. Toni Nadal described Sinner as "practically unstoppable," especially after the Italian distanced himself from the controversies surrounding his doping case.

Sinner's victory at the US Open marks a significant milestone in his career, as he now shares the four Grand Slam titles of 2024 with Carlos Alcaraz. Sinner secured victories at the Australian Open and the US Open, while Alcaraz claimed titles at Roland Garros and Wimbledon.Today, he has become a player who is practically unstoppable for the vast majority of his opponents. He is capable of delivering each of his strokes with great speed and of making very few unforced errors," Toni Nadal wrote in his column for El Pais."In the week before the start of the competition we were wondering how the incessant controversy generated by his possible double doping

could affect him. After the final and his magnificent performance, the Italian has shown once again that he not only has one of the best games on the circuit but also has the temperament to face really complicated situations," Toni Nadal added.

However, Toni Nadal expressed concerns about Alcaraz's ability to handle the mental challenge posed by Sinner's rapid rise. After an outstanding start to 2024, including wins at Wimbledon and Roland Garros, Alcaraz's momentum faltered following his loss to Novak Djokovic in the Paris Olympics gold medal match."I must say that I still enjoy Alcaraz' game more - I like him even more - but I must also admit and fear that the current leader's notable improvement, especially on a mental level, will make things really difficult for him. The rivalry is definitely on," Toni Nadal added.

This defeat was followed by unexpected early exits at the Cincinnati Masters and the US Open, raising questions about Alcaraz's capacity to manage mental pressure in crucial matches.Despite these setbacks, Alcaraz has shown signs of resilience, beginning his Davis Cup 2024 campaign with a strong victory over Czech tennis star Tomas Machac, who retired in the third set due to cramps. This win has fueled speculation that the 22-year-old is poised to make a robust comeback to his winning form.As the competition between Sinner and Alcaraz intensifies, Toni Nadal's insights highlight the mental and physical battles that lie ahead for both rising stars in the tennis world.

Shubman Gill training hard in gym ahead of IND vs BAN Test series

New Delhi. Shubman Gill geared up for the upcoming big Test season as he trained hard in the gym. In a video, Gill was spotted sweating it out in the gym as he engaged in a hard-core workout. He would be aiming to be at his utmost fitness as India would be having a gruelling season, which included 10 Tests this year. Gill's training involved a mix of both cardio and weightlifting exercises as he looked charged up during the session. Gill would also have a huge responsibility on his shoulders, given he would bat at the No. 3 position.Gill, considered as one of the next all-format star players, opened up about not being able to meet his expectations fully. He made his Test debut later in December 2020 during the Test series against Australia. He managed to score runs at an average of 35.52 and has scored 4 hundreds and 6 fifties in 25 matches.

"Yes, I've not been up to my own expectations ([n Test cricket]," he told PTI on the eve of the

Duleep Trophy opener in Bengaluru. "But we have ten Tests coming up together. Hopefully, after these ten Tests end, I'd be up to my expectations or more," he added.The 25-year-old had started his career as an opener but has now taken up the role of No.3, following in the footsteps of Rahul Dravid and Cheteshwar Pujara. While there were a few difficult moments for Gill during the England series earlier in the year at home, he was able to turn a corner and score 2 hundreds and finished as the second highest run-getter in the series with 452 to his name from 5 matches.Earlier, there were doubts whether Gill, a traditional opener, would be able to transition into the new role. However, slowly but surely, he proved himself as India's No. 3 batter. However, his biggest challenge would be the upcoming 5-match Test series against Australia. He would aim to be in good form and the foundation of which would be laid in the Bangladesh and New Zealand Test series, which would be played at home.

Recalling Bangladesh's Test debut vs India: Dhaka witnesses history in 2000

New Delhi The 1999 ODI World Cup holds special memories for Bangladesh. It started with Aminul Islam Bulbul's men taking down a red-hot Pakistan at the County Ground in Northampton. With the likes of Saeed Anwar, Inzamam-ul-Haq and Wasim Akram in their ranks, beating Pakistan wasn't a walk in the park back then, but the Tigers did the unthinkable and neutralized their opponents.On the back of their impressive showing, Bangladesh got Test status in June 2000. Later that year, they made history after playing their maiden Test match against India, captained by Sourav Ganguly. Naimur Rahman Durjoy had the honour of captaining Bangladesh in front of a packed house at the Bangabandhu National Stadium in Dhaka.India went into the game as the favourites and they won by nine wickets, a result which wasn't any different from expectations. But it was Aminul Islam, who etched his name in the history of Bangladesh cricket by becoming their first centurion. He scored 145 runs off 380 balls with 17 fours and helped his team post an impressive 400 in their very first Test innings.Skipper Naimur also made history, becoming the first Bangladeshi with a five-wicket haul in Test cricket. With figures of 44.3-9-132-6, Durjoy allowed India to take a lead of only 29 runs. The match was well and truly in the balance until the opening session of the fourth day. But then, gap of experience between the two teams showed.

India bowled their opponents out for 91 in 46.3 overs and set themselves a target of 63. Rahul Dravid's brisk 49-ball knock of 41 made sure that India romped past the finish line in 15 overs. Sunil Joshi walked away with the Player of the Match award after he took five wickets in the first innings followed by a three-wicket haul.

Bangladesh yet to open their account

Since 2000, India and Bangladesh have faced each other 13 times in Test cricket. While India have won 11 times, the Tigers are yet to get on the board. Habibul Bashar and Mushfiqur Rahim are the Bangladeshi skippers to have led their team to draws in 2007 and 2015 respectively.Back in December 2022, Bangladesh got close to beating India for the first time in Test cricket. They gave themselves a more than realistic chance of pulling off a massive heist at the Sher-e-Bangla National Stadium in Mirpur.Defending 145 in the fourth innings.

R Ashwin begins hunt of Glenn McGrath, Nathan Lyon's records in Bangladesh Tests

Legendary India spinner R Ashwin will resume his international season with the Test series against Bangladesh. Ashwin, who has 516 wickets to his name has been the standout bowler at home in recent years.

New Delhi India spinner Ravichandran Ashwin will resume his international season with the home Test matches against Bangladesh. Ashwin, who has 516 wickets to his name in the red-ball format will be eyeing to clasp a few more in the series vs Bangladesh and New Zealand before flying out to Australia to play the Border-Gavaskar Trophy.The mystery spinner is one of India's finest bowlers of all time and has been especially effective in the last three years. It is not like Ashwin has had a dip in form ever in home Tests, but since 2021, Ashwin has 109 wickets at home nearly double that of the next-best Indian bowler - Ravindra Jadeja - who has 56 wickets.Ashwin, who is easily one of the two greatest spinners in the Test format in recent times, will hope to solidify his position in the echelons of history in the next 5 Test matches. At the moment, Ashwin's tally of 516 wickets puts him in the 9th position among all-time wicket-takers in Test history.

Can Ashwin surpass McGrath?

Immediately ahead of Ashwin, there are Courtney Walsh (519), Nathan Lyon (530) and Glenn McGrath (563). It is a real possibility that Ashwin will chase down Lyon's tally in the home Tests itself, which will give a nice flavour to the Border Gavaskar Trophy, set to begin in the month of November.Apart from Lyon and McGrath, Ashwin is also chasing Stuart Broad in a different list altogether. Ashwin, who has 363 wickets at home will look to go ahead of Broad, who has 398, while playing in Test matches at home in England.In fact, Lyon is the greatest home spinner of all time, where he took over Anil Kumble (350) in the previous series against England. Ashwin picked 26 wickets in 5 matches against the Ben Stokes side. If he continues the same touch, he might just pull off a stunner andgo over Broad in 2024 itself.Ashwin will have a fantastic support cast around him including the likes of Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, Jadeja and Axar Patel. The spinner will hope for a terrific precursor to the Border-Gavaskar Trophy, potentially his final one in Australian soil. Ashwin has 39 wickets in Australia in 10 Test matches and is expected to be one of the main threats Down Under due to his experience and guile.The mystery spinner, who is in his last legs in international cricket will hope to secure his legacy as one of the best of all time in the next run of 10 Test matches before potentially playing the World Test Championship Final in Lord's.

Shilpa Shetty

Is Ageing Like A Fine Wine And We Have Proof

Shilpa Shetty Kundra never ceases to amaze people with her impeccable fashion sense. At 49, the Bollywood actress still can give the young actresses a run for their money with her toned physique and stunning looks. Recently, Shilpa mesmerised everyone with her looks in a beautiful silk saree. The paparazzo page Viral Bhayani shared a video of Shilpa on the set of a show, where she was seen walking in a multicoloured silk saree featuring a beaded, shimmery border. She paired the saree with a heavily embroidered and multicoloured half-sleeved blouse, perfectly complementing her vibrant lookShilpa opted for pearl-studded sandals, a heavy polki necklace, a nose pin and two oxidised bracelets to accessorise her look. Meanwhile, she kept her soft-curled hair open in a middle partition and used shimmery eyeshadow and nude lipstick to finish off her look.

On Tuesday, Shilpa was spotted with her husband, Raj Kundra and her mother as they offered their prayers at Lalbaugh Cha Raja. In several paparazzi videos, the actress looked resplendent in a simple red-striped saree featuring a golden border. She paired the saree with a matching blouse and opted for heavy pieces of jewellery. Most notably, the actress and her husband walked barefoot to the pandal.Like every year, Shilpa and Raj welcomed Ganpati to their home with much pomp and zeal this time. In a post shared on her Instagram account, the actress was seen in festive spirits along with her husband and daughter. She was seen wearing a Johari skirt set from Punit Balana's collection. Her outfit comprised an embroidered waistcoat, tissue skirt and dual-toned contrasting dupatta. Sharing the post, Shilpa wrote, Opening our hearts and doors to welcome Bappa, Favorite time of the year."

Meanwhile, on the day of Ganpati Visarjan, Shilpa twinned with her daughter, Samisha, in a mustard yellow floral shararas and choli sets. The actress opted for earrings and adorned her well-tied braid with latkans. In the video that she shared on her Instagram account, the entire family was seen offering prayers before bidding adieu to Lord Ganesha.

Sharing the video, Shilpa wrote, "Never easy to say goodbye to our Gannu Raja. We bid him farewell with heavy hearts, but full of gratitude and love. Can't wait to welcome you next yearOn the work front, Shilpa was last seen in Rohit Shetty's Indian Police Force alongside Vivek Oberoi and Sidharth Malhotra. She will be next seen in the Kannada film KD-The Devil.

Neha Gowda

And Pavithra Gowda Flaunt Pregnancy Glow In Viral Pic

Kavitha Gowda and Neha Gowda started their Kannada television journey with Lakshmi Baramma in 2013. It is the second longest-running television show in the Kannada television industry. It has two seasons. Apart from the lead actresses, the serial also starred Chandan Kumar, Vijay Suroya, Deepa Ravishankar, Bhagyashri Rao and Vijay in the lead roles.Neha Gowda recently announced her pregnancy in a heartwarming video with her husband Chandan Kumar. Coincidentally, Kavitha Gowda is also expecting her first child now. She congratulated the actress and said that she is feeling grateful to share her happy moments with her dear friend Kavitha Gowda. She posted a bunch of pictures in which they were seen hugging each other with matching outfits. The photos have gone viral now.

In the latest viral post of Neha Gowda, the actress is seen posing with Kavitha Gowda. The duo shared a joyous moment as they both cherished their unborn babies. The actresses donned similar sarees with pink and green borders. Neha Gowda was seen wearing a green pearl necklace while Kavitha Gowda donned gold plated necklace. In the series of pictures, the actresses looked like sisters. On this occasion, the actress Neha Gowda wrote, "I feel grateful to have shared my pregnancy journey with my little one, and now she's expecting her baby soon! Wishing her a happy, healthy, and safe delivery. May this new chapter bring immense joy and happiness to her life!" Take a look at the post,The fans flocked to the comments section of the post to congratulate the actress for her post. Kavitha Gowda replied, 'To the both of us' on the post. One of the users pointed out that the saree worn by the actress has also been used in the popular serial Lakshmi Baramma. "Neha madam you wore this saree in Lakshmi Baramma serial right," wrote one of the users.Kavitha Gowda debuted in the film industry with the film Srinivasa Kalyana in 2017. It is directed by MG Srinivas who also appears in the lead role.

Karan Sharma On Wife Surbhi Chandna's 35th Birthday: 'My Reason To Be'

Fans and celebrities have flooded social media with heartfelt birthday wishes for Surbhi Chandna as she turned 35 today. However, the sweetest message came from her husband Karan Sharma who posted a touching video encapsulating the couple's 14-year journey together. Attached to the clip was a short but sweet caption that read, "Happy Birthday My Reason To Be."The wholesome clip opens with Karan Sharma playing the "Happy Birthday" tune on the piano for his loving wife Surbhi Chandna. Sitting beside him and smiling, the birthday girl is visibly excited. Then, it cuts to a glimpse of Karan's smartwatch which displays the picture of the actress as the wallpaper. As the clock strikes midnight, he pans the camera towards Surbhi and says, "Happy birthday, baby. 12 baj gaye." The couple is seen seated inside a plane, seemingly heading for a holiday to ring in the television star's birthday.

As the clip proceeds, a message then flashes on-screen reading, "Life with you is like a never-ending vacation. Happy Birthday to the one who makes me fall in love with her every day." Attached next are cute glimpses wherein the married couple is seen engrossed in some sweet moments as Karan adorably carries his ladylove on his back and takes her out on a date night. Do not miss the highlights from their pre-wedding shoot and the one where Surbhi lovingly feeds Karan a biscuit. The video concludes with another note reading, "14 years and counting."

Fans and followers were quick to shower the cute couple with love and adoration. One user wrote, "Everything is so beautiful here," while another mentioned, "The caption brought a wide smile on my face."

Meena Kumari And Kamal Amrohi's Love Story To Be Turned Into Film, Sanjay Dutt Wishes Luck

The untold love story of legendary actor Meena Kumari and filmmaker Kamal Amrohi is set to come to the big screen. Directed by Siddharth P Malhotra, the film, titled Kamal Aur Meena, will explore the couple's timeless journey, delving into their personal lives as well. Officially announced as a joint project by Saregama and Bilal Amrohi, Kamal Amrohi and Meena Kumari's grandson, the news has garnered attention. Actor Sanjay Dutt extended his heartfelt wishes to Bilal and his wife, Saachi Kumar Amrohi, following the announcement.Sharing the announcement teaser on his Instagram handle, Dutt wrote, "Dear Saachi and Bilal, all the best for your new venture. May it be a successful one! Love always, from Sanjay Mamu. It's a must-watch."

For those unaware, Saachi Kumar Amrohi is the daughter of Namrata Dutt, sister of the Bollywood actor. Both Saachi and Bilal have joined the project as producers, states a Pinkvilla report.

Speaking about the video, it begins with a series of vintage pictures of the late actor along with some letters in Urdu. What follows are the voices of Meena and Kamal in the background as they call out to each other with some endearing nicknames. "A filmmaker, A Muse, Their star crossed love story, A dream that refused to die, A love that went beyond the grave," read the on-screen captions amid the music of Chalte Chalte from Pakeezah.

More Details About 'Kamal Aur Meena'

While the Maharaj director takes on the project, it also involves a star-studded lineup of talents like AR Rahman, Irshad Kamil, Bhavani Iyer, and Kausar Munir.

Speaking to Zoom, Siddharth P Malhotra revealed that the entire Amrohi family will be a part of the project.

"They are producing it. The casting will be done in November," he added. Bilal Amrohi also shared his views and said that he wishes to show their "heart-wrenching" story to the world. "Over 500 handwritten letters exchanged between my grandparents Kamal Sahaab and Meenaji, as well as personal journals detailing their lives together," he said, as quoted by Hindustan Times.